PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-02 ● अंक- 05 ● भिलाई, शनिवार 18 जुलाई 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

संक्षिप्त समाचार

बिहार के मुंगेर में बेटी के अपहरण का केस नहीं लिया वापस, अपहणकर्ताओं ने गोली मारी

पटना। बिहार के मुंगेर जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अपराधियों ने पहले एक युवकी का अपहरण किया और जब युवती के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस में दी तो उनकी हत्या कर दी गई। घटना फियासराय थाना क्षेत्र की है। यहां के डकरा सतखजुरिया गांव स्थित एक ईंट-भट्ठे पर 45 वर्षीय सुबोध कुमार यादव बुधवार रात को ड्यूटी कर रहे थे। तभी कुछ लोग आए और उनके सिर पर गोली मारकर फरार हो गए। सुबोध यादव की नाबालिग बेटी का मई में गायब हो गई थी। इसके बाद उन्होंने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। कुछ लोगों का कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का था, जबकि सुबोध ने इसे अपहरण का मामला बताकर नामजद शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी का परिवार सुबोध से नाराज था और बदला लेने की सोच रहा था।

गुजरात में तीन मिनट में दो बार आया भूकंप

अहमदाबाद। गुजरात के कच्छ जिले में तीन मिनट के अंतराल पर दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र कच्छ जिले में धोलावीरा से 32 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में स्थित था. रिक्टर पैमाने पर पहले आए भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई जबकि दूसरा झटका 3.2 की तीव्रता का रहा. हालांकि दोनों भूकंप की तीव्रता अधिक नहीं थी लेकिन लोगों ने कंपन को महसूस किया. पहला भूकंप दोपहर 2:20 बजे दर्ज किया गया. इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई. भूकंप का केंद्र खावड़ा से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित था. झटके हल्के थे, लेकिन कई इलाकों में लोगों ने कंपन महसूस किया. कुछ लोग एहतियात के तौर पर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए. पहले झटके के ठीक तीन मिनट बाद, 2:23 बजे दूसरा भूकंप आया.

कांग्रेस राम मंदिर, पेपर लीक और एथनॉल के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी

नई दिल्ली। कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार को शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी अनियमितता, पेपर लीक, राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी, एथनॉल, परिसीमन से जुड़े विषय तथा कई अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी. पार्टी का यह भी कहना है कि वह इस सत्र में विदेश नीति के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े विषय को भी प्रमुखता से उठाएगी. इसी क्रम में पार्टी की संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10, जनपथ पर एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे.

विधानसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव

डॉ. महंत ने गिनाई सरकार की विफलताएं विधायक अजय चंद्राकर के तीखे बोल...

रायपुर। संवाददाता

विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने 136 बिंदुओं वाला अविश्वास प्रस्ताव सामने रखते हुए जमकर विष्णुदेव साय सरकार की विफलताएं गिनाई। वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर तीखे बोल बोले। डॉ. महंत व चंद्राकर ने एक-दूसरे की नाकामी के कई उदाहरण गिनाए। अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात शुरु करते हुए डॉ. महंत ने कहा कि विष्णु देव साय सरकार को 136 हफ्ते हो गए। हम 136 बिन्दुओं वाला आरोप पत्र लेकर आए हैं। डॉ. महंत ने अविभाजित मध्यप्रदेश के समय के पूर्व मंत्री संत कवि पवन दीवान की कविता का अपने भाषण में उल्लेख किया-

चुप-चुप रहकर
सब कुछ सहकर
सबका मान बढ़ाते हैं
बार-बार अपमानित होकर
गैरों का गुणगान कराते हैं
मेहमानों को खूब खिलाकर
चुपचाप सो जाते हैं
इसलिए ही छत्तीसगढ़िया
परबुद्धि कहलाते हैं
छत्तीसगढ़ में सब कुछ है
लेकिन कमी है स्वाभिमान की
मुझसे सही नहीं जाती
ऐसी चुप्पी वर्तमान की...

कविता की परबुद्धि वाली लाइन का डॉ. महंत व्दारा उल्लेख किये जाने पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी एवं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताई और कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ऐसी राय कायम नहीं की जाती। डॉ. महंत ने कहा ये मेरा लिखा नहीं है। ये संत पवन दीवान की कविता है। डॉ. महंत ने मंत्री ओ.पी. चौधरी की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि आप कब पैदा हुए यह मुझे मालूम न, लेकिन यह सच है कि

'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया' नारा मेरे पिता का दिया हुआ है। हम छत्तीसगढ़ की मूल भावना को सामने रखे रहे हैं तो दूसरों को क्यों पीड़ा हो रही है। डॉ. महंत ने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव किसान, महिलाओं, युवाओं के खिलाफ रचे गए षड़यंत्र का दस्तावेज है। 1963 में आचार्य जे.पी. कृपलानी ने नेहरू सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास पेश किया था। तब खुद नेहरू जी ने उसका स्वागत करते हुए कहा था कि सरकार के ख़िलाफ़ लोकतंत्र में ऐसी स्वस्थ बहस होती रहनी चाहिए। ये अच्छी परम्परा है। 1979 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ये महसूस हुआ कि सदन में उनकी पहले जैसी स्थिति नहीं रही, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही इस्तीफ़ा देना स्वीकार कर लिया। डॉ. महंत ने कहा कि 26 जुलाई 2022 को हम लोगों ने एक अहम् निर्णय लिया था। सर्वसम्मति से एक संकल्प लाया था कि हसदेव में आबंटित कोल ब्लॉक को रद्द करते हैं। इस सरकार के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की शपथ भी नहीं हुई थी कि उससे पहले हसदेव अरण्य को काटने का सिलसिला शुरू हो गया। हसदेव अरण्य को मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। यह वहां के आदिवासियों की आस्था का प्रतीक है। मंत्रि मंडल के अस्तित्व में आने से पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों ने हसदेव को ब्लॉक को खनन के लिए सौंप दिया। पंद्रह हज़ार पेड़ों की कटाई शुरु हो गई। जिस रास्ते से भगवान राम गुज़रे उसे उद्योगपति को सौंप दिया गया और हमारे हिस्से में क्या आया हाथी-मानव संघर्ष। डॉ. महंत ने कहा कि कोरिया जिले में 29 वर्षीय महिला का बलात्कार कर उसे ज़िंदा जला दिया गया। अपनी बात रखने थाने पहुंचे एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डाला गया। राखी के दिन मुख्यमंत्री के क्षेत्र में रेप की घटना हो गई। इसे जंगल राज न कहें तो क्या कहें। यह सरकार अहंकार में डूबी हुई है। पिछले सरकार के कार्यकाल के न जाने कितने ही कामों को रोक दिया गया। केवल जेब भरने का कार्यक्रम चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछले ढाई साल में सबसे ज्यादा अहित किसानों का हुआ। बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को छत्तीसगढ़ को सौंप देने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, लेकिन पेसा क़ानून की राज्य में क्या हालत है? जहां खनन का काम हो रहा वहां से आदिवासी भगाए जा रहे हैं। राज्य में भू माफ़िया बढ़ गए हैं। ये पैतृक जमीनें तक छिन ले रहे हैं। अबूझमाड़ में जंगलों की कटाई शुरू हो चुकी है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता रहा, लेकिन धान के उत्पादन में यहां के किसान खून के आंसू रो रहे हैं। जो अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ वह यह सरकार कर ले रही है। धान ख़रीदी में गड़बड़ी की लगातार शिकायतें आती रही हैं। जशपुर जिले के पचास हज़ार पंजीकृत किसानों में से आठ हज़ार किसान अपना धान नहीं बेच पाये। डॉ. महंत ने कहा कि भारतमाला परियोजना में पाँच सौ करोड़ रुपए से ज़्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है। एक खसरे के कई-कई टुकड़ों में बेचा गया। हमारे पैसों में भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसका दोष मैं किसे दूँ? मनमोहन सिंह की सरकार में वनभूमि अधिनियम बना था। पट्टा देने का प्रावधान किया था। इसे भी आप नहीं कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना की वजह से आपकी सरकार बनी। अगर ये योजना नहीं बनती तो आपका राम नाम सत्य हो गया था। बच्चों तक में शराबखोरी की लत पड़ रही है। लगता है एक महीने में एक हज़ार करोड़ रुपये की शराब पिलाकर एक नया कीर्तिमान बनाना चाह रहे हैं। एक मंत्री का वीडियो है मेरे पास, जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि शराब से जो पैसा आता है, उसे ही हम महतारी वंदन में देते हैं। डॉ. महंत ने आरोप लगाया कि ग़रीब के बच्चों को पढ़ाना बंद किया जा रहा है। दस हज़ार स्कूल बंद कर दिए गए। शिक्षकों की कमी है। एक मंत्री थे जिन्होंने कहा था कि 33 हज़ार स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होगी।

वधुओं को नकली मंगलसूत्र पहनाए जाने का मामला विधानसभा में उठा

रायपुर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में वधुओं को नकली मंगलसूत्र पहनाए जाने के मामले को कांग्रेस विधायक श्रीमती अनिला भेंड़िया ने आज विधानसभा में उठाया। प्रश्नकाल में श्रीमती अनिला भेंड़िया का सवाल था कि 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के तहत बालोद जिले में पिछले दो वर्षों में कुल कितने सामूहिक विवाह आयोजित हुए उन पर कुल कितना व्यय हुआ वित्तीय सहायता में से उपहार सामग्री और विशेष रूप से आभूषण मंगलसूत्र, बिछिया आदि के लिए प्रति जोड़ा कुल कितनी राशि निर्धारित है क्या विभाग को उपहार सामग्री की गुणवत्ता में भारी कमी और वित्तीय विसंगतियों के कारण सप्लायर फर्म के बिलों से कटौती (रिकवरी) करनी पड़ी है यदि हाँ, तो कितनी क्या उक्त फर्म को ब्लैक लिस्ट में डाला गया क्या वहाँ वितरित सामग्री की गुणवत्ता की कोई लैब टेस्टिंग या वित्तीय ऑडिट कराया गया है यदि नहीं, तो शासन इस गंभीर लापरवाही की उच्च स्तरीय या थर्ड पार्टी जांच कब तक कराएगी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की ओर से जवाब आया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बालोद जिले में पिछले दो वर्षों में कुल 07 सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। उन पर कुल 1 करोड़ 99 लाख 95 हजार 294 रुपये की राशि व्यय हुई। योजनांतर्गत प्रति जोड़ा उपहार सामग्री अंतर्गत श्रृंगार सामग्री हेतु राशि 7 हजार रुपये की व्यय सीमा निर्धारित है। जिसके अंतर्गत वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी, साफा, मंगलसूत्र इत्यादि सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्री का प्रावधान है। प्रति हितग्राही मंगलसूत्र, बिछिया आदि हेतु पृथक से लागत राशि निर्धारित नहीं है। सप्लायर फर्मों के बिलों से कटौती रिकवरी जैसी स्थिति नहीं रही। वितरित सामग्री की गुणवत्ता की कोई लैब टेस्टिंग या वित्तीय ऑडिट नहीं कराया गया है। गंभीर लापरवाही के प्रकरण प्राप्त न होने से उच्च स्तरीय या थर्ड पार्टी जांच की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं है। श्रीमती अनिला भेंड़िया ने कहा कि आपने गलत आंकड़े पेश किए।

चंडीगढ़ पर मां चंडी का लिया आशीर्वाद

यहां का विकास पूरे उत्तर भारत के लिए अहम-पीएम मोदी.....

चंडीगढ़/ संवाददाता

पीएम ने कहा कि चंडीगढ़ केवल एक शहर नहीं भारत के डेवलपमेंट के लिए एक मॉडल है। चंडीगढ़ की पहचान बेहतर लाइफस्टाइल, चिकित्सा सुविधा के लिए। मां चंडी के आशीर्वाद के लिए भी इसकी पहचान है। चंडीगढ़ का विकास हमेशा एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। पीएम ने कहा कि हमने देश में न्याय संहिता में बड़ा बदलाव किया। भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत चंडीगढ़ से हुई। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल, स्मार्ट पार्किंग, डिजिटल गवर्नमेंट ऐसे कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए। ढाई हजार करोड़ से ज्यादा खर्च किया। अब नए प्रोजेक्ट पर खर्च किया गया है। मोदी ने कहा कि मेरे लिए स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान बहुत अहम है। उन्होंने चंडीगढ़ के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू की सफाई अभियान की तारीफ की। मोदी ने कहा कि मैं देख रहा था कि मेरे आने से पहले नेता शहर में सफाई अभियान चला रहे थे। मोदी ने कहा कि एक समय था, जब भारत के हेल्थ सेक्टर पर दुनिया सवाल उठाती थी। कोरोना के समय में हमने देखा कि भारत के लिए विश्व का नजरिया बदला। भारत मदद मांगने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को मदद दे रहा था। भारत मेडिकल डेस्टिनेशन बन रहा है। बारह साल पहले हमने संकल्प लिया था कि देश को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। जेपी नड्डा ने कहा कि ये शहर पीएम का अपना शहर है, ये उनकी कर्म भूमि रही है।

महाराष्ट्र के वर्धा में नाबालिग लड़की की हत्या, यौन उत्पीड़न की आशंका, तीन गिरफ्तारी

वर्धा। महाराष्ट्र के वर्धा में नाबालिग लड़की की हत्या करने का मामला सामने आया है. उसका शव बिना कपड़ों के मिला है. इससे यौन उत्पीड़न की आशंका जताई जा रही है. गृह राज्य मंत्री ने इस मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. वर्धा जिले के सवांगी पुलिस स्टेशन थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 साल की एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पत्थर से कुचलकर मार डाला गया. चूंकि उसकी बिना कपड़ों की बॉडी एक फार्महाउस में मिली, इसलिए सेक्सुअल असॉल्ट का भी शक है. इस घटना से इलाके में गुस्सा फैल गया है और गांव में तनाव का माहौल है. इस बीच, गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा, इस घटना के बारे में केस दर्ज कर तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सोनम वांगचुक का नया वीडियो सामने आया

मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा उसके बाद भूत बनकर आऊंगा

नई दिल्ली/ एजेंसी

कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी समर्थन दे रहे हैं। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर है। कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेता ने सोनम वांगचुक से मुलाकात कर उनके प्रदर्शन को समर्थन दिया है। इस बीच वांगचुक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सोनम वांगचुक कर रहे हैं कि मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर आप लोगों के बीच आऊंगा। वांगचुक ने यह बात मजाकिया अंदाज में कही। संसद तक की मार्च का जिक्र करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, जिससे आप सभी के साथ संसद तक मार्च कर सकूं। अगर 20 जुलाई को हमारा मार्च सफल नहीं रहा तो फिर भूतकर बनकर वापस आऊंगा। बता दें कि नीट परीक्षा लीक और सीबीएसई विवाद को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। लद्दाख के इंजीनियर, शिक्षाविद् और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए थे। तभी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। लगातार भूखे रहने के कारण उनका वजन लगातार घट रहा है।

बिलासपुर में 20 साल बाद बाढ़ जैसे हालात

मूसलाधार बारिश से सड़कें और घर जलमग्न,पांच ट्रेनें रद्द हुए

- एसडीआरएफ ने 40 से अधिक लोगों का किया रेस्क्यू

बिलासपुर। संवाददाता

बिलासपुर में गुरुवार रात से शुक्रवार दोपहर तक लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। करीब 20 साल बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। लगातार बारिश के कारण शहर के अधिकांश इलाके पानी में डूब गए हैं। सड़कों से लेकर कॉलोनियों तक जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है, जबकि रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से 5 मेमू ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 3 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान औसतन 74.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 110.2 मिमी वर्षा सीपत क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार लगातार हो रही बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। सरकंडा और चांटीडीह के निचले इलाकों में पानी तेजी से भरने के कारण 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सरकंडा के बंधवापारा क्षेत्र में एसडीआरएफ की टीम ने दो नावों की

मदद से राहत एवं बचाव अभियान चलाया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं, दोमुहानी इलाके में 10 से अधिक घर चारों ओर से पानी से घिर गए, जिससे कई परिवार पूरी रात अपने घरों में फंसे रहे। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद राहत दल मौके पर पहुंचा और लोगों को सुरक्षित निकालने की कार्रवाई शुरू की गई। शहर के कई हिस्सों में ट्रांसफॉर्मर पानी में डूब जाने से बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। कई इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। बिजली आपूर्ति ठप होने से पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित हुई है और लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग की टीमें हालात सामान्य करने में जुटी हुई हैं। भारी बारिश का असर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी दिखाई दिया। बिलासपुर कलेक्टर के सरकारी बंगले में भी पानी भर गया, जिसके बाद नगर निगम की टीम को जल निकासी के लिए लगाया गया। नगर निगम की मशीनें लगातार पानी निकालने का काम कर रही हैं ताकि स्थिति जल्द सामान्य हो सके।

नेशनल हाईवे पर भी जलभराव, वाहनों की लगी लंबी कतार

बिलासपुर-जांजगीर नेशनल हाईवे पर दरौंधाट के पास बारिश का पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हो गया। मूसलाधार बारिश के बीच वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीरों ने जलभराव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं अपोलो हॉस्पिटल के पास भी जलभराव के कारण लोग घंटों तक फंसे रहे। काफी मशक्कत के बाद लोग सुरक्षित बाहर निकल सके। बारिश थमने के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे, हालांकि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला अधिवक्ता संघ ने मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि शुक्रवार को बारिश के कारण किसी भी मामले में प्रतिकूल आदेश पारित न किए जाएं।

नवोदय प्रवेश परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का होगा पंजीयन बालिकाओं की सहभागिता बढ़ाने पर विशेष जोर

गरियाबंद। कलेक्टर बीएस उइके के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी राजेश चन्द्राकर, जवाहर नवोदय के प्राचार्य महिमा सिन्हा द्वारा जिले के सभी बीईओ एवं एबीईओ की नवोदय विद्यालय पाण्डुका में कक्षा 6 वीं प्रवेश चयन परीक्षा हेतु शत-प्रतिशत आवेदन सुनिश्चित करने के लिए बैठक ली गई। बैठक में आगामी नवोदय प्रवेश चयन परीक्षा के लिए जिले के प्रत्येक पात्र विद्यार्थियों तक पहुंच बनाकर शत-प्रतिशत आवेदन भरवाने एवं निर्धारित समय-सीमा में जमा कराने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से बालिकाओं की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा गया कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाओं को नवोदय विद्यालय जैसी उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्था में अध्ययन का अवसर दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए यह आवश्यक है कि जिले का कोई भी पात्र विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा से वंचित न रहे। इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए विद्यालय स्तर पर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने, पालकों से संपर्क स्थापित करने तथा विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया एवं परीक्षा के महत्व की जानकारी देने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बालिकाओं की सहभागिता बढ़ाने विशेष जोर दिया गया है। बैठक में नोडल अधिकारी सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को संकुल समन्वयकों, प्रधान पाठकों एवं शिक्षकों के माध्यम से विशेष अभियान संचालित कर अधिक से अधिक विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं, को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

लैण्ड बैंक की जानकारी के पुनः सत्यापन के निर्देश

गरियाबंद। कलेक्टर बीएस उइके की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में लैण्ड बैंक की जानकारी के सत्यापन एवं पुनः सर्वेक्षण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में उपलब्ध लैण्ड बैंक की वर्तमान स्थिति, अभिलेखों के सत्यापन, मैदानी सर्वेक्षण तथा अद्यतन जानकारी तैयार करने की प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान वनमण्डलाधिकारी शशिगानंदन के., अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे, ऋषा ठाकुर सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनभूमि के व्यपवर्तन के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लैण्ड बैंक की जानकारी का अद्यतन किया जाना जरूरी है। इसके लिए जिले में उपलब्ध गैर वनभूमि, राजस्व वन भूमि तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप अन्य उपयुक्त भूमि का सत्यापन कर नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनः चिन्हांकन किया जाएगा। कलेक्टर उइके ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लैण्ड बैंक से संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि का राजस्व एवं वन विभाग संयुक्त रूप से सत्यापन करें तथा सभी अभिलेखों, नक्शों और मैदानी स्थिति का मिलान करते हुए त्रुटिरहित जानकारी शीघ्र तैयार करें।

उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रपत्रों में समस्त जानकारी समय-सीमा के भीतर संकलित कर अद्यतन डाटा तैयार किया जाए, जिससे विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संबंधी कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि चयनित भूमि का सर्वेक्षण निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए।

समूह की महिलाओं को मिला पैरा आर्ट का प्रशिक्षण

बलौदाबाजार। जिले की महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण एवं उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम लाहौद में 40 महिलाओं को धान एवं पैरा आर्ट का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सम्पन्न होने पर सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने महिलाओं द्वारा तैयार किये गये विभिन्न कलाकृति का अवलोकन कर प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत बिहान टीम के संयुक्त प्रयास से गैर कृषि आजीविका को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ महतारी संकुल संगठन लाहौद में धान एवं पैरा आर्ट में शामिल समूह की 40 दीदियों को प्रशिक्षण दिलाया गया।

जिले मे अब तक औसत वर्षा 294.7 मि.मी. दर्ज

गरियाबंद। चालू मानसून सत्र में एक जून से 16 जुलाई 2026 तक जिले की औसत वर्षा 294.7 मि.मी. दर्ज की गई है। गत वर्ष (पिछले 10 वर्ष के आधार पर) इस अवधि तक 358.1 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी। भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसीलवार 16 जुलाई 2026 की स्थिति में सर्वाधिक वर्षा राजिम तहसील में 446.5 मि.मी दर्ज की गई है। इसी प्रकार छुरा तहसील में 359.7 मि.मी., फिंगेश्वर तहसील में 349.2 मि.मी., मैनपुर तहसील में 316.2 मि.मी. और गरियाबंद तहसील में 299.3 मि.मी., देवभोग तहसील में 166.2 मि.मी. एवं अमलीपदर तहसील में 125.7 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। पिछले दस वर्षों के आधार पर 1 जून से आज तक की औसत वर्षा 358.1 मि.मी. है।

कलेक्टर उइके की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की हुई बैठक सम्पन्न

किसान 31 जुलाई तक करा सकेंगे फसल बीमा

गरियाबंद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कलेक्टर बीएस उइके की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा अंतर्गत किसानों को फसल बीमा आवरण में शामिल करने मैदानी स्तर पर व्यापक प्रचार करने निर्देश दिए गए है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2026 हेतु अधिसूचना जारी की गई है। जिले के लिए खरीफ मौसम में धान सिंचित एवं असिंचित, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, कोदो, कुटकी, रागी फसलों को अधिसूचित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी भू-धारक कृषक, बटाईदार एवं वनपट्टाधारी कृषक ले सकते हैं। गरियाबंद जिले में फसल बीमा के लिए बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अनुबंधित किया गया है। जारी अधिसूचना में कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार फसल कैलेंडर में भी संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन की एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए सभी पात्र किसानों से फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अपील की गई है। इस वर्ष अल-नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए मानसून के देर से आने, समय से पहले समाप्त होने तथा फसल अवधि के दौरान लंबे समय तक वर्षा नहीं होने जैसी परिस्थितियां बनने की संभावना है। ऐसे में फसल बीमा किसानों के लिए जोखिम से बचाव का एक बेहतर विकल्प है। खरीफ मौसम 2026 के लिए बीमा राशि निर्धारित किया गया है, जिसमें अनाज, दलहन एवं तिलहन फसल हेतु कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत तथा लघुधान्य फसलों हेतु 01 प्रतिशत किसानों द्वारा प्रीमियम के रूप में देना होगा। धान सिंचित फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 66 हजार रुपये निर्धारित की गई है, जिसके लिए किसान अंश प्रीमियम 1320 रुपये प्रति हेक्टेयर होगा।

मौसमी बीमारियों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी

लक्षण दिखने पर तत्काल उपचार और सूचना की अपील, ग्रामीणों से सीधे जुड़ कर किया जा रहा संवेदीकरण

बलौदाबाजार। मानसून के मौसम में बारिश के पानी के जमा होने, नमी बढ़ने और जल-जमाव के कारण विभिन्न संक्रामक रोग तेजी से फैलते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील ज़ारी की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश अवस्थी ने बताया कि बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के साथ ही डायरिया, टाइफाइड, पीलिया जैसे जल जनित अन्य रोग भी आम हैं। इन रोगों से बचाव के लिए ही जिला संपर्क केंद्र के माध्यम से ग्राम पंचायतों से ऑनलाइन जुड़ कर संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसमें सम्बंधित ग्राम वासियों और जन प्रतिनिधियों को रोग से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। आईडीएसपी के जिला नोडल अधिकारी डॉ नवदीप बांधे के अनुसार दस्त और उल्टी वाले रोगों में बार-बार दस्त, उल्टी, पेट में ऐंठन और निर्जलीकरण की समस्या हो सकती है। इनसे बचने के लिए पीने का पानी उबालकर या फिल्टर करके पिएँ, खाना अच्छी तरह पकाकर खाएँ और हाथों को साबुन से बार-बार धोएँ।

गांव में पेयजल स्रोतों की सफाई भी जरूरी है। ऐसे ही मच्छर जनित रोगों से बचाव हेतु कहीं जल जमाव न होने दें साथ ही मच्छरदानी का उपयोग करें। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधक सृष्टि मिश्रा ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है साथ ही किसी आवश्यकता पर 104 पर कॉल करने की सलाह दी है।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने जापान से लौटी छात्राओं का किया स्वागत

धमतरी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की दो होनहार छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमतरी सहित पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रोशन किया है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत जापान के वैज्ञानिक भ्रमण से वापस लौटने पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने इन छात्राओं का स्वागत किया। सम्मानित होने वाली छात्राओं में सुनैना साहू और समीक्षा साहू शामिल हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर वैश्विक पटल पर पहचान बनाई है। इस गौरवशाली उपलब्धि की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो इस वर्ष इंस्पायर मानक स्कीम सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम ऑफ जापान के लिए देशभर से कुल 56 विद्यार्थियों का चयन किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य से कुल पांच छात्राओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिला, जिसमें सबसे खास बात यह रही कि धमतरी जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल कोसमर्रा से ही दो छात्राओं ने इस सूची में अपनी जगह बनाई। साव ने कहा कि हमारे प्रदेश की बेटियाँ अपनी प्रतिभा और नवाचार से विश्व पटल पर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा रही हैं। जापान के सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम से लौटने पर धमतरी जिले की प्रतिभाशाली छात्राओं कुमारी सुनैना साहू एवं कुमारी समीक्षा साहू से आत्मीय भेंट कर उनका स्वागत एवं सम्मान करने का अवसर मिला। इस उपलब्धि में मार्गदर्शन देने वाले शिक्षकों एवं सहयोगी टीम का योगदान भी अत्यंत सराहनीय है। इन बेटियों की सफलता इस बात का प्रमाण है कि अवसर और सही मार्गदर्शन मिलने पर हमारे ग्रामीण अंचलों की प्रतिभाएँ भी वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकती हैं। दोनों छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। विश्वास है कि आप आगे भी अपनी प्रतिभा से प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाती रहेंगी।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की रेशमा शेख बनीं कांकेर जिला प्रभारी

धमतरी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा छग की संभाग, जिला प्रभारी, सहप्रभारी की घोषणा की गई है जिसमें धमतरी निवासी रेशमा शेख को कांकेर जिले का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सहप्रभारी के रूप में रायपुर निवासी परवेज कुरैशी को नियुक्त किया गया है। रेशमा शेख पिछले कई वर्षों से भाजपा के लिये समर्पित होकर कार्य कर रही हैं। उनकी पार्टी के प्रति समर्पण एवं सक्रियता को देखते हुए उन्हें पार्टी द्वारा नवागांव वार्ड से भाजपा प्रत्याशी बनाया गया था। शेख को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री सहित पश्चिमंदा मुस्लिम संघ के प्रदेश अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया था जिसमें उन्होंने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया जिसके चलते एक बार फिर उन्हें कांकेर जिले का प्रभारी बनाया गया है। रेशमा शेख के इस नियुक्ति पर प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष शशि ठाकुर, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रकाश बैस, महापौर रामू रोहरा, महामंत्री महेंद्र पंडित, राकेश साहू, कविंद्र जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता हाजी बशीर अहमद, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष आबिद अली, नवनियुक्त एल्डरमेन अरविंदर सिंह मुंडी, दिलीप पटेल, रीतिका यादव सहित भाजपा के अनेक नेता, कार्यकर्ताओं ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

हिमानी की उपस्थिति में लाल बगीचा वार्ड में सतनाम समाज द्वारा नव-निर्मित जैतखाम चबूतरे का हुआ पूजन

धमतरी। लाल बगीचा वार्ड क्रमांक 03 में सतनाम समाज द्वारा नवनिर्मित जैतखाम चबूतरे का विधि-विधान एवं श्रद्धा-भक्ति के साथ पूजन-अर्चन संपन्न किया गया। जैतखाम सतनाम, सत्य, समानता और शांति का प्रतीक माना जाता है तथा सतनाम समाज की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। इस पावन अवसर पर नगर निगम धमतरी की विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सभापति एवं लाल बगीचा वार्ड क्रमांक 03 की पार्षद हिमानी भागवत साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में सतनाम समाज के वरिष्ठजनों, मातृशक्ति एवं युवाओं ने पुष्पगुच्छ एवं पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत एवं सम्मान किया। मुख्य अतिथि हिमानी भागवत साहू ने सतनाम समाज को नव-निर्मित जैतखाम चबूतरे की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक स्थल समाज की एकता, सदभाव और सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त बनाते हैं। उन्होंने समाज के विकास एवं जनहित के कार्यों में सदैव सहयोग देने का विश्वास भी व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने समाज की सुख-समृद्धि, क्षेत्र की उन्नति एवं सर्वजन कल्याण की मंगलकामना करते हुए पूजन.अर्चन में सहभागिता निभाई।

भगवान जगन्नाथ महापर्व रथ यात्रा पर महापौर ने दी शुभकामनाएं

धमतरी। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पावन रथ यात्रा महापर्व के शुभ अवसर पर नगर पालिक निगम धमतरी के महापौर जगदीश रामू रोहरा ने समस्त नगर एवं जिलेवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। महापौर रामू रोहरा ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा भारतीय संस्कृति, आस्था, सेवा, समर्पण और सामाजिक समरसता का महान प्रतीक है। यह महापर्व सभी समाजों को एक सूत्र में जोड़ते हुए प्रेम, भाईचारे और सदभाव का संदेश देता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं माता सुभद्रा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का संचार हो तथा प्रदेश और देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहे। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से धमतरी नगर सहित पूरे प्रदेश में खुशहाली, समृद्धि और जनकल्याण का वातावरण बना रहे।

महापौर ने नागरिकों से रथ यात्रा महापर्व को श्रद्धा, उत्साह एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने तथा सामाजिक एकता और भाईचारे को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। महापौर रामू रोहरा ने भगवान जगन्नाथ से सभी नागरिकों के सुखमय, समृद्ध एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हुए एक बार पुनः रथ यात्रा महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

राम मंदिर में चंदा चोरी, कांग्रेस ने लगाये अनेक गंभीर

भाजपा करती है धर्म की राजनीतिः शैलेष नितिन त्रिवेदी

धमतरी। मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम, करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति, नैतिक चेतना के प्रतीक हैं। देश के कोने-कोने में गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं और श्रद्धालू अपने मेहनत की कमाई, अपने गहने, अपनी बचत और अपनी श्रद्धा लेकर राम मंदिर निर्माण के लिये आगे आये। भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के संगठनों ने लगभग तीन दशकों तक भगवान राम के नाम पर राजनीति की। देश के गरीब व मध्यम वर्ग से राम के नाम पर चंदा एकत्र किया और इसी आंदोलन के आधार पर सत्ता हासिल की। लेकिन अब भगवान राम के नाम पर जुटाया गया चंदा भी भाजपा, आरएसएस की राजनीतिक लूट का जरिया बन गया। यह बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर धमतरी पहुंचे शैलेष नितिन त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता में कही। राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता का शुभारंभ जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष तारिणी नीलम चंद्राकर के द्वारा किया गया। उन्होंने इस प्रेस कांफ्रेंस के लिये नियुक्त शैलेष नितिन त्रिवेदी के आगमन को लेकर संक्षिप्त में जानकारी दी, पश्चात त्रिवेदी ने उपरोक्त बातें कहीं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि चंदा चोरी को लेकर करोड़ों रामभक्त यह पूछने पर मजबूर हैं कि भगवान राम के नाम पर जुटाया गया चंदा और चढ़ावा आखिर किसके संरक्षण में लूटा गया। यह केवल आर्थिक घोटाला नहीं है, यह करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था, भावना, विश्वास के साथ किया गया घोर विश्वासघात है। भाजपा रामद्रोही है। उसने पहले चंदा में हेराफेरी करवाया, अब चढ़ावा में चोरी। भाजपा ने राम मंदिर निर्माण के समय रामशिला पूजन के नाम से जो 1400 करोड़ से अधिक राशि एकत्रित की, उसका जवाब आरएसएस एवं भाजपा के लोग नहीं दे पाये। उनके ही सहयोगी नेताओं ने ही राम मंदिर निर्माण के समय एकत्रित किये चंदे का आरोप लगाया था। जिन लोगों ने मंदिर बनाने के नाम पर चंदा में हेराफेरी किया था, वही लोग मंदिर बनने के बाद चढ़ावे में हेराफेरी करने लगे। इन सबकी पृष्ठभूमि में आरएसएस और भाजपा का ही नाम सामने आ रहा है। कहा जा सकता है कि इन घोटालों को आरएसएस, भाजपा का संरक्षण मिल रहा है। भाजपा ने देवद्रव्य चोरी करने के महापाप को संरक्षण दिया है। राम मंदिर न्याय ट्रस्ट का गठन गृहमंत्री अमित शाह ने किया था। इसलिये वहां घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी मोदी और शाह की बनती है। पाठ्यपुस्तक के पूर्व अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने आगे पत्रकारों को संबोधित करते हुए तीन बड़े सवाल भी किये जिनमें ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ, तो इस घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा? अगर सब कुछ ठीक था तो चंपतराय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे क्यों हुए, अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से डर किस बात का है? उन्होंने अब तक सामने आये तथ्यों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपतराय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किये जा चुके हैं। यह स्वयं इस बात का संकेत है कि मामला सामान्य प्रशासनिक त्रुटि का नहीं, बल्कि एक बड़े घोटाले का है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से बयान दिये हैं जबकि ट्रस्ट की वित्तीय निगरानी पारदर्शिता, संपत्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च जिम्मेदारी उन्हीं की थी। मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए त्रिवेदी ने आगे यह भी कहा कि ट्रस्ट के विशिष्ट आमंत्रित सदस्य गोपाल राव (गोपाल नगरकोटे) को हटाये जाने और उनकी स्थिति को लेकर भी गंभीर भ्रम और विरोधाभास सामने आये हैं। आरएसएस के पूर्व उत्तर प्रदेश प्रभारी कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया जो आरएसएस के पूर्वी उत्तरप्रदेश प्रभारी हैं, उन्हें इस प्रकरण को दबाने और लीपापोती करने के आरोप सार्वजनिक रूप से लगाये जा चुके हैं। यह जग जाहिर है कि ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे और शीर्ष नियुक्तियों में प्रधानमंत्री कार्यालय की सक्रिय भूमिका रही। ऐसे में केंद्र सरकार अपनी जवाबदारी से स्वयं को अलग नहीं कर सकता। एसआईटी अब राम मंदिर के बड़े आयोजनों के खर्चों की भी जांच कर रही है। इसी तरह अनेक गंभीर आरोप लगाये गये हैं। अब देश जानना चाह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी मौन क्यों हैं? पत्रकार वार्ता में शैलेष नितिन त्रिवेदी के अलावा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तारिणी नीलम चंद्राकर, मोहन लालवानी, अरविंद दोषी, पूर्व विधायक लक्ष्मी ध्रुव, कविता बाबर, आनंद पवार, सूर्याराव पवार, रजत जसूजा, विक्रांत पवार, कृष्ण कुमार मरकाम, विशु देवांगन, राकेश मौर्य, योगेश शर्मा, शास्त्री सोनवानी समेत अनेक कांग्रेसजन उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

विधानसभा में नक्सलवाद के खात्मे पर आभार प्रस्ताव, शहीदों को नमन और विकास का संकल्प

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नक्सलवाद के खिलाफकेंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों, पुलिसकर्मियों और निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि नक्सलवाद की वजह से दशकों तक बस्तर सहित कई क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रभावित रहीं। रानीबोदली, ताड़मेटला, झीरम घाटी और अन्य बड़े नक्सली हमलों का उल्लेख करते हुए शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। सरकार ने दावा किया कि वर्ष 2024 से 2026 के बीच नक्सली घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। इस अवधि में 537 नक्सली मारे गए, 2,055 गिरफ्तार हुए और 2,948 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। साथ ही नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता, आवास, प्रशिक्षण और रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रस्ताव में बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक, नियद नेल्लानार योजना और सेवा डेरा जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इन पहलों से आदिवासी क्षेत्रों में विकास, खेल, संस्कृति और सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ी है। सड़क, रेल, मोबाइल टावर और अन्य बुनियादी ढांचे के विस्तार पर भी सरकार ने जोर दिया। प्रस्ताव के अंत में सभी दलों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास में सहयोग की अपील की गई और नक्सल हिंसा के खिलाफ अपने प्राण न्योछावर करने वाले सभी वीर जवानों एवं नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

भाजपा ओबीसी मोर्चा ने संभाग प्रभारियों और सहप्रभारियों की घोषणा की

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) मोर्चा छत्तीसगढ़ ने संगठनात्मक विस्तार को गति देने के लिए संभाग प्रभारी एवं सहप्रभारियों की घोषणा की है। यह नियुक्तियां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से जारी की गई हैं। जारी सूची के अनुसार दुर्ग, सरगुजा, बस्तर, रायपुर और बिलासपुर संभाग के लिए प्रभारी एवं सहप्रभारियों की नियुक्ति की गई है। संगठन का उद्देश्य प्रदेशभर में ओबीसी मोर्चा को और अधिक सक्रिय बनाना तथा संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करना है। सूची के अनुसार दुर्ग संभाग के प्रभारी राजेंद्र जायसवाल एवं सहप्रभारी तुलसी साहू, सरगुजा संभाग के प्रभारी होरीलाल सिन्हा, बस्तर संभाग के प्रभारी हेमराज सोनी, रायपुर संभाग के प्रभारी चुन्नीलाल साहू एवं सहप्रभारी नरोत्तम साहू, तथा बिलासपुर संभाग के प्रभारी शांतनु साहू एवं सहप्रभारी आशीष जायसवाल बनाए गए हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने विश्वास जताया है कि नई टीम संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद बढ़ाने और पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

शराब के लिए पैसे मांगकर युवक से मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने बड़पारा शराब भट्ठी के पास युवक से शराब पीने के लिए पैसे मांगकर मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को घटना के कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अजमानतीय धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, 13 जुलाई 2026 को ईतवारी बाजार के पास बड़पारा निवासी भरत सिंह ध्रुव (24) ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे वह बड़पारा शराब भट्ठी में शराब खरीदने गए थे। इसी दौरान शराब भट्ठी के बाहर मौजूद बिट्टू सारथी, अन्जू बनसदा और आकाश चौहान ने उन्हें रोककर शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब भरत सिंह ने पैसे देने से इनकार किया तो तीनों आरोपियों ने उनके साथ अश्लील गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ पकड़कर मुक्कों से मारपीट कर घायल कर दिया। शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 373/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(3), 115(2), 119(1) एवं 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश चौहान (19) निवासी चांदनी चौक गांडा पारा, अन्जू बनसदा (35) निवासी चमड़ा गोदाम वार्ड क्रमांक-38 तथा बिट्टू सारथी (25) निवासी वार्ड क्रमांक-11, चांदनी चौक, फारूकी गली, रायगढ़ शामिल हैं। जांच में तीनों की प्रवृत्ति पूर्व से झगड़ा-विवाद करने की पाई गई। न्यायालय में पेश करने के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर गुंडागर्दी करने और आम नागरिकों के साथ मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

युवाओं को कौशल विकास अपनाने और नशे से दूर रहने का आह्वान

रायपुर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर बुधवार को शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, कारंजी, विकासखंड तोकापाल, जिला बस्तर में कौशल विकास एवं नशा मुक्ति विषयक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में कौशल विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उन्हें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका के प्रति प्रेरित करना तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए जनजागरूकता उत्पन्न करना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर के प्रभारी बी. एस. ध्रुव ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी तभी प्रभावी होगी, जब वे शिक्षा के साथ कौशल विकास को भी अपनाएं। उन्होंने कहा कि कौशल भारत मिशन (स्किल इंडिया मिशन) युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने कौशल को निरंतर विकसित करने, नई तकनीकों को अपनाने तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। बी एस ध्रुव ने नशा मुक्त भारत अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ट्री एटीएम को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

आज लगाया गया हर पौधा आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित का आधार

- वन विभाग की अभिनव पहल से नि:शुल्क पौधों का होगा वितरण, पर्यावरण संरक्षण का दिया जाएगा संदेश

रायपुर/ संवाददाता

आमतौर पर एटीएम का नाम सुनते ही लोगों के मन में पैसे निकालने वाली मशीन की तस्वीर उभरती है, लेकिन जशपुर वन विभाग ने पर्यावरण संरक्षण को जन-जन का अभियान बनाने की दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए 'ट्री एटीएम' की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बगिया हेलीपैड परिसर में इस अनूठे मोबाइल ट्री एटीएम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल आम नागरिकों तक पौधों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एवं जनजागरूकता को नई गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर स्वयं ट्री एटीएम से आंवला का पौधा प्राप्त किया तथा उपस्थित लोगों को भी पौधों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि यह मोबाइल ट्री एटीएम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर आम नागरिकों को नि:शुल्क पौधे उपलब्ध कराएगा। इससे अधिक से अधिक लोग पौधरोपण से जुड़ेंगे और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनभागीदारी को नया विस्तार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर वन विभाग की इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि 'ट्री एटीएम' लोगों को सहज और सरल तरीके से पौधे उपलब्ध कराने का एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वर्षा ऋतु पौधरोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय है। ऐसे समय में यह पहल लोगों को विभिन्न प्रजातियों के पौधे आसानी से उपलब्ध कराएगी, जिससे व्यापक स्तर पर पौधरोपण को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए 'एक पेड़ मां के नाम' महाअभियान ने पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति नई चेतना का संचार किया है। इसी अभियान से प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ में भी व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसके वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल का संकल्प ले, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक पौधरोपण कर 'एक पेड़ मां के नाम' महाअभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि 'एक पेड़ मां के नाम' महाअभियान के अंतर्गत प्रारंभ किए गए ट्री एटीएम को 'आज का पौधा, आने वाली पीढ़ियों की छांव' के प्रेरक संदेश के साथ रवाना किया गया। इस अभिनव पहल के तहत केवल नि:शुल्क पौधों का वितरण ही नहीं किया जाएगा, बल्कि पौधा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पौधरोपण की वैज्ञानिक एवं सही विधि, नियमित देखभाल, संरक्षण तथा पौधे को वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखने के उपायों की भी जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उनके संरक्षण और जीवित रहने की दर को बढ़ाना है, ताकि पर्यावरण संरक्षण का यह अभियान दीर्घकालिक और प्रभावी बन सके।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव हेल्पलाइन और सेवा सेतु से बदली हजारों लोगों की जिंदगी....

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु आम नागरिकों के लिए भरोसेमंद मंच बनकर उभरे हैं। इन माध्यमों से प्रदेशभर में लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ अब नागरिकों को पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल और तेज़ी से मिल रहा है। दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम ओरी निवासी श्री अभिषेक चतुर्वेदी लंबे समय से अपनी पत्नी श्रीमती शीतल चतुर्वेदी का राशन कार्ड बनवाने का प्रयास कर रहे थे। संबंधित विभाग में आवेदन देने के बावजूद विभिन्न कारणों से राशन कार्ड जारी नहीं हो पा रहा था, जिससे परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित था। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की और कुछ ही दिनों में राशन कार्ड जारी कर दिया। राशन कार्ड मिलने पर परिवार ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हेल्पलाइन ने उनकी बड़ी समस्या का शीघ्र समाधान कर उन्हें राहत पहुंचाई। इसी तरह खैरागढ़ जिले की श्रीमती शमाबाई कुमुद रामटेके लंबे समय से आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं से परेशान थीं। कई प्रयासों और कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद उनका कार्य नहीं हो सका था। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करने के बाद अधिकारियों ने तत्काल संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। उनके आधार कार्ड में पते की त्रुटि का सुधार किया गया, बायोमेट्रिक अपडेट कराया गया और पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर उन्हें राहत प्रदान की गई। श्रीमती शमाबाई ने समय पर समाधान मिलने पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और प्रशासन के प्रति संतोष एवं आभार व्यक्त किया। वहीं, खैरागढ़ जिले के ग्राम पचपेड़ी निवासी श्री इन्द्रेश कुमार विश्वकर्मा को इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए तत्काल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। समय पर दस्तावेज नहीं मिलने से उनका प्रवेश प्रभावित होने की आशंका थी। ऐसे में उन्होंने सेवा सेतु के माध्यम से आवेदन किया। प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उसी दिन आवेदन का परीक्षण कर निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जिससे उनका इंजीनियरिंग प्रवेश सुरक्षित हो सका।

मनरेगा का चेक डेम बना किसानों की नई उम्मीद पहुंचेगा सिंचाई का पानी

- एमसीबी के माड़ीसरई में अंधेरगढ़ नाला पर बनी स्थायी जल संरचना, भूजल संरक्षण के साथ खेती और रोजगार को मिलेगा नया संबल

रायपुर/ संवाददाता

कभी बारिश का पानी बह जाने से गर्मी में जल संकट झेलने वाले मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत माड़ीसरई के किसानों के लिए अब हालात बदलने की उम्मीद जगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अंधेरगढ़ नाला पर निर्मित पक्का चेक डेम गांव में जल संरक्षण और सिंचाई का स्थायी आधार बनकर उभरा है। इससे लगभग 12.5 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है। ग्रामीणों के अनुसार पहले बरसात का अधिकांश पानी नाले के जरिए बह जाता था। इसके कारण गर्मी के दिनों में खेतों और पेयजल दोनों के लिए संकट पैदा हो जाता था। अब चेक डेम बनने से वर्षा जल का संचयन होगा और किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस परियोजना के निर्माण में 1,185 मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ। इससे गांव के श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर काम मिला और रोजगार के लिए बाहर पलायन की जरूरत भी कम हुई। निर्माण कार्य में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। चेक डेम से केवल सिंचाई ही नहीं, बल्कि भूजल स्तर में सुधार की भी उम्मीद है। वर्षा जल के संरक्षण से आसपास के कुओं और हैंड पंपों में पानी की उपलब्धता बढ़ने के साथ मिट्टी के कटाव पर भी नियंत्रण मिलेगा। इससे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। ग्रामीण किसानों का कहना है कि अब वे केवल वर्षा आधारित खेती तक सीमित नहीं रहेंगे। सिंचाई सुविधा मिलने से धान के अलावा दलहन, तिलहन और अन्य फसलों की खेती का दायरा भी बढ़ सकेगा, जिससे कृषि उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि होने की संभावना है। ग्रामीणों के अनुसार यह चेक डेम केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि गांव की कृषि व्यवस्था को स्थायी आधार देने वाली परिसंपत्ति है। इससे जल संरक्षण, रोजगार और खेतीकृतीनों क्षेत्रों में दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है। माड़ीसरई का यह मॉडल इस बात का उदाहरण बन रहा है कि यदि मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण स्थानीय जरूरतों के अनुरूप किया जाए, तो ग्रामीण विकास, जल संरक्षण और किसानों की आर्थिक मजबूती जैसे कई लक्ष्य एक साथ हासिल किए जा सकते हैं।

एक फोन कॉल ने लौटाई किसान की उम्मीद

सीएम हेल्पलाइन 1076 से समय पर मिली खाद-प्रहलाद साहू.....

रायपुर/ संवाददाता

एक संवेदनशील सरकार की पहचान केवल योजनाएं बनाने से नहीं, बल्कि जरूरत के समय आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने से होती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 आज छत्तीसगढ़ में सुशासन, जवाबदेह प्रशासन और जनविश्वास का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। यह व्यवस्था लोगों को घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कराने और उसके समयबद्ध निराकरण की सुविधा प्रदान कर रही है। कबीरधाम जिले के ग्राम वीरेंद्रनगर निवासी किसान श्री प्रहलाद साहू का अनुभव बताता है कि संवेदनशील शासन व्यवस्था किस प्रकार समय पर लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रही है। खरीफ सीजन में श्री प्रहलाद साहू को खेती के लिए खाद की जरूरत थी। उन्होंने खाद वितरण केंद्र में सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए थे और बायोमेट्रिक सत्यापन भी करा लिया था। इसके बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा था। समय पर खाद नहीं मिलने से उन्हें अपनी खेती की चिंता होने लगी। इसी दौरान उन्हें सीएम हेल्पलाइन 1076 के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने टोल-फ्री नंबर पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद उन्हें शिकायत क्रमांक मिला और संबंधित विभाग ने मामले पर कार्रवाई शुरू की। लगभग एक सप्ताह के भीतर उनकी शिकायत का समाधान हो गया और उन्हें आवश्यक खाद यूरिया, डीएपी, पोटाश और सुपर फास्फेट उपलब्ध करा दिया गया। श्री प्रहलाद साहू कहते हैं कि मैं बहुत परेशान था।

टिकरापारा पुलिस की कार्रवाई, अवैध शराब बेचते युवक को रंगे हाथ गिरफ्तार

रायपुर। डीसीपी वेस्ट जोन के निर्देश पर थाना टिकरापारा पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संतोषी नगर स्थित सीरत मैदान के पास एक युवक को अवैध शराब बेचते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 5.940 लीटर (33 पौवा) देशी मदिरा बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि संतोषी नगर निवासी दिनेश सागर अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मरई के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई। पुलिस ने सीरत मैदान के पास आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी कर उसे 33 पौवा गोवा एवं शोले ब्रांड की देशी मदिरा के साथ गिरफ्तार किया।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में छत्तीसगढ़ ने बनाया राष्ट्रीय कीर्तिमान

मंत्री राजवाड़े ने साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में छत्तीसगढ़ ने बनाया राष्ट्रीय कीर्तिमान
- 14.49 लाख से अधिक माताओं को 558.93 रूपये करोड़ की डीबीटी सहायता

रायपुर/ संवाददाता

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सशक्त बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बनाने में सफल रहा है। पारदर्शी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली, राज्य सरकार की सतत निगरानी तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्पित प्रयासों से प्रदेश की लाखों गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तक समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने योजना की इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ मातृ सुरक्षा, पोषण और महिला कल्याण के क्षेत्र में लगातार नए मानक स्थापित कर रहा है। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि प्रदेश में अब तक 14 लाख 49 हजार 309 पात्र हितग्राहियों का सफल पंजीयन किया जा चुका है। इन सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 558.93 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी भुगतान व्यवस्था के कारण लाभार्थियों को बिना किसी बिचौलिये के समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना विश्व की सबसे बड़ी डीबीटी आधारित मातृत्व सहायता योजनाओं में से एक है। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की केस स्टडी के अनुसार यह योजना गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है। योजना के सकारात्मक प्रभाव से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाने में भी सहायता मिली है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व, बेहतर पोषण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है। इसी उद्देश्य से विभाग द्वारा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है तथा पात्र हितग्राहियों का समयबद्ध पंजीयन सुनिश्चित किया जा रहा है। योजना की सफलता के बीच मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने साइबर अपराधियों की सक्रियता को लेकर प्रदेशवासियों को विशेष रूप से सचेत किया। उन्होंने बताया कि कुछ जिलों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर फर्जी फोन कॉल कर महिलाओं से ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी अथवा राशि की मांग किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा, ष्यदि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर ओटीपी, बैंक संबंधी जानकारी या किसी प्रकार की राशि की मांग की जाती है, तो उसकी बातों में बिल्कुल न आएं। ऐसे कॉल साइबर ठगों के हो सकते हैं। किसी भी संदिग्ध स्थिति में तत्काल अपनी निकटतम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा संबंधित विभाग से संपर्क करें। साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय जागरूकता और सतर्कता ही है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हितग्राही महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए।

संपादकीय

भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का नया अध्याय, रक्षा से परमाणु ऊर्जा तक बढ़ा सहयोग

पिछले कुछ समय के दौरान मुक्त व्यापार के क्षेत्र में भारत ने कई देशों के साथ समझौते किए हैं, जिसके तहत देश की अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए नई संभावनाएं तैयार करने की कोशिश की गई है।वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अलग-अलग देशों में आपसी सहयोग के लिए जिस स्तर पर नए समीकरण बन रहे हैं, उससे साफ है कि अब पुराने ध्रुवों के विकल्प तैयार हो रहे हैं और विकसित तथा सक्षम देशों को भी अपने बेहतर भविष्य का रास्ता तैयार करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में देखें, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को जिस स्तर पर सहयोग और साझेदारी की घोषणा हुई, वह मौजूदा दौर की जरूरतों के मद्देनजर एक महत्त्वपूर्ण पहल है।गौरतलब है कि पिछले कुछ समय के दौरान मुक्त व्यापार के क्षेत्र में भारत ने कई देशों के साथ समझौते किए हैं, जिसके तहत देश की अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए नई संभावनाएं तैयार करने की कोशिश की गई है। इसी क्रम में अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती देने जैसे कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है।साथ ही परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, साइबर तकनीक, अंतरिक्ष और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग का दायरा बढ़ाने का खाका भी पेश किया गया। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने तथा अन्य मोर्चों पर जारी तनावों के हल के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयास जारी रखने पर भी सहमति बनी।जाहिर है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझेदारी के सफर के विस्तार की जो पहल हुई है, उसका आधार अगले कुछ दशकों में वैश्विक स्तर पर आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर बदलते ध्रुव और उसी मुताबिक तैयार होते समीकरण हैं, जिनमें सहयोग के नए आयाम तैयार हो रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का पहले से ही साझेदारी का लंबा सफर रहा है, लेकिन ताजा समझौतों में परमाणु ऊर्जा और दुर्लभ खनिजों के मामले में सहयोग के जिस मोर्चे पर ठोस समझदारी बनी है, वह आने वाले वक्त में बेहद अहम साबित हो सकती है।ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया भर के यूरेनियम संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा है, मगर कुछ कानूनी और तकनीकी अड़चनों की वजह से भारत को अब तक इसका लाभ नहीं मिल सका। अब ताजा समझौते के बाद भारत को अपनी परमाणु ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ईंधन का एक अहम स्रोत मिल सकेगा।हालांकि मौजूदा दौर में विश्व जिस स्तर के तनावों से गुजर रहा है, उसमें यूरेनियम के उपयोग को लेकर आशंकाएं स्वाभाविक हैं। मगर इस मसले पर दोनों देशों ने यह साफ किया है कि सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम निर्यात की अनुमति होगी और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तय सुरक्षा प्रावधानों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही दोनों देश खनिज गलियारे को विकसित करने के क्षेत्र में भी साझेदारी करेंगे, जिससे चीन पर निर्भरता कम होगी।

देश को नक्सल आतंक की जकड़ से बाहर निकालने और जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अगले चरण का बिगुल फूंक दिया है। इस बार निशाने पर केवल घुसपैठ नहीं, बल्कि घुसपैठ के जरिये सीमावर्ती इलाकों में बदलता जनसंख्या संतुलन, तस्करी, मादक पदार्थों का जाल, कट्टरपंथ, ड्रोन खतरे, संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित छद्म युद्ध की पूरी रणनीति है। अमित शाह ने स्पष्ट संकेत दिया है कि देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने और सीमाओं को अभेद्य सुरक्षा कवच देने का व्यापक अभियान अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अमित शाह का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन केवल स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और सामरिक संतुलन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ऐसे में यह अभियान वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के भारत की सुरक्षा का भी मजबूत आधार बनेगा।

नक्सलवाद के बाद घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार, अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अगले चरण का बिगुल फूंका

(नीरज कुमार दुबे)

नई दिल्ली में आयोजित सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीमा सुरक्षा के लिए सरकार की नई और व्यापक रणनीति सामने रखी। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सीमा सुरक्षा के समग्र दृष्टिकोण को संस्थागत स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देश को नक्सल आतंक की जकड़ से बाहर निकालने और जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अगले चरण का बिगुल फूंक दिया है। इस बार निशाने पर केवल घुसपैठ नहीं, बल्कि घुसपैठ के जरिये सीमावर्ती इलाकों में बदलता जनसंख्या संतुलन, तस्करी, मादक पदार्थों का जाल, कट्टरपंथ, ड्रोन खतरे, संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित छद्म युद्ध की पूरी रणनीति है। अमित शाह ने स्पष्ट संकेत दिया है कि देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने और सीमाओं को अभेद्य सुरक्षा कवच देने का व्यापक अभियान अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अमित शाह का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन केवल स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और सामरिक संतुलन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ऐसे में यह अभियान वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के भारत की सुरक्षा का भी मजबूत आधार बनेगा। हम आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीमा सुरक्षा के लिए सरकार की नई और व्यापक रणनीति सामने रखी। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सीमा सुरक्षा के समग्र दृष्टिकोण को संस्थागत स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब केवल भूमि सीमाओं तक ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में तटीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी इसी प्रकार का समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सम्मेलन में सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों, उनके समाधान और भविष्य की नीति तैयार करने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था अब केवल चौकियों और गश्त तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार सीमा सुरक्षा बलों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय नागरिकों को साथ जोड़कर चार स्तरीय सुरक्षा तंत्र तैयार कर रही है। यही चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था भविष्य में भारत की सीमाओं को अभेद्य बनाने का सबसे मजबूत आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर ही राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। गृह मंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत की लगभग पंद्रह हजार किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा अठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। इतनी विशाल सीमा की सुरक्षा केवल सुरक्षा बलों के भरोसे संभव नहीं है। इसके लिए स्थानीय समाज की भागीदारी, प्रशासनिक समन्वय और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग अनिवार्य है। इसी सोच के तहत सरकार अलग थलग सीमा चौकियों की पुरानी व्यवस्था से आगे बढ़कर एकीकृत सुरक्षा तंत्र विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की स्मार्ट सीमा की परिकल्पना आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे आधुनिक सीमा सुरक्षा व्यवस्था का रूप लेगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नक्सलवाद, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में हिंसा के खिलाफ उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अब अगले तीन वर्षों में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर भी निर्णायक प्रहार किया जाएगा। साथ ही ऐसा मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिससे देश पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बने और भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ की संभावना लगभग समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि पहले समस्याएं स्थायी होती थीं और समाधान अस्थायी, लेकिन अब सरकार समस्याओं की जड़ पर प्रहार कर स्थायी समाधान तैयार कर रही है। देखा जाये तो इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सीमावर्ती

क्षेत्रों में बदलते जनसंख्या स्वरूप पर मोदी सरकार का विशेष ध्यान है। अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण अवैध घुसपैठ है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या अध्ययन अभियान प्रारंभ किया है, जिसके तहत जनसंख्या में हो रहे अस्वाभाविक बदलावों का अध्ययन किया जाएगा, उनके कारणों की पहचान होगी और भविष्य में ऐसे परिवर्तनों को रोकने के उपाय सुझाए जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्वाभाविक कारणों से होने वाली जनसंख्या वृद्धि पर कठोरता के साथ नियंत्रण किया जाएगा। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना सबसे निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक तत्काल पहुंचनी चाहिए, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सरकार सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए आधारभूत ढांचे पर भी अभूतपूर्व निवेश कर रही है। अमित शाह ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में आधारभूत संरचना पर निवेश में चार सौ प्रतिशत की वृद्धि की गई है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सड़कों, संचार व्यवस्था, निगरानी तंत्र तथा अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। भारत म्यांमार सीमा के सोलह सौ दस किलोमीटर लंबे हिस्से पर 31 हजार करोड़ रुपये की लागत से बाड़ लगाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसका उद्देश्य केवल घुसपैठ रोकना नहीं, बल्कि छद्म युद्ध, अवैध हथियारों की आवाजाही, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित अन्य गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है। साथ ही मोदी सरकार की सीमा सुरक्षा नीति केवल सैन्य दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। सीमावर्ती गांवों को मजबूत बनाना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतिम गांव को पहला गांव बताया है। इस योजना के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन रोकने, स्थानीय रोजगार बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी सरकार का मानना है कि जब सीमा पर बसे गांव समृद्ध होंगे, वहां के लोग सुरक्षित और आत्मनिर्भर होंगे, तभी सीमा सुरक्षा भी स्थायी रूप से मजबूत होगी। सामरिक दृष्टि से देखें तो यह नई नीति भारत की सुरक्षा सोच में बड़ा परिवर्तन है। अब देश केवल किसी घटना के बाद प्रतिक्रिया देने की नीति पर नहीं रहेगा, बल्कि संभावित खतरों को पहले ही पहचानकर उन्हें रोकने की सक्रिय रणनीति अपनाई जाएगी। घुसपैठ, छद्म युद्ध, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रोन के जरिये हथियार पहुंचाना, साइबर अपराध और संगठित अपराध आज एक दूसरे से जुड़ी चुनौतियां बन चुकी हैं। ऐसे में इन सभी के खिलाफ एकीकृत सुरक्षा तंत्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती देगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सीमाओं पर प्रभावी नियंत्रण, जनसंख्या संतुलन की निगरानी, आधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था और सीमावर्ती गांवों का विकास एक साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बना सकेगा, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार की बाहरी चुनौती का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने की स्थिति में भी होगा। अमित शाह द्वारा प्रस्तुत यह नई रणनीति केवल सीमा सुरक्षा का कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, सामरिक शक्ति और भविष्य के भारत की सुरक्षा संरचना को मजबूत करने वाला व्यापक अभियान बनकर उभर रही है। हम आपको यह भी बता दें कि इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए अमित शाह स्वयं भी सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने सीमा चौकियों का निरीक्षण किया, सुरक्षा बलों के साथ संवाद स्थापित किया, नियंत्रण रेखा का निरीक्षण किया, भारत-पाक सीमा के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र जाकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की और महिला जवानों के लिए नई बैरकों का उद्घाटन किया। स्पष्ट है कि मोदी सरकार केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक निगरानी प्रणाली, तकनीक आधारित सुरक्षा तंत्र, मजबूत समन्वय और प्रत्यक्ष निरीक्षण के माध्यम से पूरे सीमा सुरक्षा ढांचे को नए सिरे से सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

इतिहास के निशां- बाकू की पवित्र अग्नि और भारत का प्राचीन संबंध

इतिहास के निशां- बाकू की पवित्र अग्नि और भारत का प्राचीन संबंध

(अभय कुमार)

वर्तमान मंदिर परिसर इन घुमंतू समुदायों की सक्रियता को दर्शाता है। सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बाकू में बसे पंजाब के हिंदू खत्री व्यापारियों द्वारा पुनर्निर्मित, यह मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में, बल्कि व्यापारिक नेटवर्क द्वारा समर्थित एक संस्थागत केंद्र के रूप में भी कायम रहा। बाकू के बाहरी इलाके में स्थित सुराखानी के हवादार मैदानों में, एक शांत ली आज भी उस सभ्यतागत स्मृति को रोशन करती है, जो कैस्पियन सागर के तटों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक फैली हुई है। प्राचीन अतेशगाह अग्नि मंदिर में कभी धरती से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली यह अग्नि मात्र एक भौगोलिक घटना नहीं थी। सदियों से, यह भारतीय आस्था, गतिशीलता और आध्यात्मिक कल्पना के लिए एक पवित्र आधार रही है, जो इसकी भौगोलिक उत्पत्ति से कहीं आगे तक फैली हुई है। अपने संलग्न प्रांगण, केंद्रीय वेदी और सादगीपूर्ण कक्षों वाले इस मंदिर परिसर में आज भी स्पष्ट भारतीय छाप दिखाई देती है- नटराज से संबंधित मूर्तियों से लेकर गणेश जी का आह्वान करने वाले शिलालेखों तक- जो यह दर्शाते हैं कि यह महज एक आकस्मिक संपर्क क्षेत्र नहीं बल्कि एक व्यापक पवित्र भूगोल का जीवंत विस्तार था। प्रवेश कक्ष, जिसके ऊपर एक कमरा या अतिथि कक्ष बना हुआ है, कभी हिंदू और सिख तीर्थयात्रियों के ठहरने का स्थान हुआ करता था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सुराखानी न केवल एक पूजा स्थल था बल्कि एक सक्रिय तीर्थ केंद्र भी था जो लंबी दूरी के व्यापार और धार्मिक मार्गों से जुड़ा हुआ था। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि ससानियन काल (224-651 ईस्वी) के दौरान बाकू को भगवान के नाम से जाना जाता था जिसे बागवान या बागुआन भी लिखा जाता था। माना जाता है कि यह नाम वैदिक लोगों द्वारा दिया गया था जो इस क्षेत्र में आए या बसे थे। इसी नाम से देश का आधुनिक नाम अजरबैजान भी बना है (अजर- अग्नि, बेगुआन - ईश्वर)। नामकरण की यह निरंतरता पश्चिम की ओर अग्नि-पूजा करने वाले आर्य समूहों के प्रारंभिक आंदोलनों द्वारा आकारित गहरे सांस्कृतिक आदान-प्रदान की ओर इशारा करती है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जलकार्बन के छिद्र, जिनसे स्वतः उत्पन्न होने वाली ज्वालाएं निकलती थीं, ने एक दुर्लभ पारिस्थितिक वातावरण बनाया जहां भूविज्ञान स्वयं धर्मशास्त्र की पुष्टि करता प्रतीत होता था, जिससे पवित्र स्थलों का एक वर्ग अस्तित्व में आया जहां अग्नि के माध्यम से दिव्य अनुभव किया जाता था। ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित प्रो. के.टी.एस. साराओ की एक रोचक पुस्तक, 'बाकू का शाश्वत अग्नि मंदिर', इस बहुआयामी इतिहास का विस्तृत दस्तावेजीकरण करती है। यह अध्ययन अतेशगाह को भारतीय अग्नि पूजा की निरंतरता में रखता है और सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्व के खंडहरों पर निर्मित वर्तमान संरचना को ज्वाला-जीभ वाली देवी ज्वाला जी से जुड़े एक बहुत पुराने पवित्र भूभाग के हिस्से के रूप में पहचान दिलाता है। इस तीर्थस्थल से जुड़ी पौराणिक कथाएं इसे भारतीय पवित्र कल्पना में दृढ़ता से स्थापित करती हैं। परंपरा के अनुसार, जब सती ने आत्मदाह किया, तो शोकग्रस्त शिव उनके शरीर को पूरे ब्रह्मांड में ले गए, जब तक कि विष्णु ने हस्तक्षेप नहीं किया और उसे कई पवित्र स्थलों में विभाजित नहीं कर दिया। जिन स्थानों पर देवी को शाश्वत ज्वाला के रूप में प्रकट होते देखा गया है, उनमें ज्वालामुखी मंदिर, शक्तिनगर, मुक्तिनाथ और बाकू में सुराखानी शामिल हैं।

सुराखानी सहित इन स्थलों पर, देवी को सात या नौ ज्वालाओं के रूप में प्रकट होते देखा गया है, जो निरंतर जलती रहने वाली दिव्य अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्राकृतिक अग्नि और पवित्र आस्था के इस अंतर्संबंध ने बाकू को पश्चिमी काशी के रूप में विख्यात कर दिया। अविभाजित भारत के हिंदू-विशेष रूप से मुल्तान के व्यापारी और तीर्थयात्री-कठिन मार्गों से न केवल पूजा-अर्चना के लिए, बल्कि कुछ मामलों में सचेत रूप से मृत्यु को स्वीकार करने के लिए भी यात्रा करते थे, जहां प्राकृतिक रूप से उत्पन्न पवित्र अग्नि का उपयोग करके दाह संस्कार किया जाता था और सुराखानी को मुक्ति की एक व्यापक आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम बिंदु माना जाता था। वर्तमान मंदिर परिसर इन घुमंतू समुदायों की सक्रियता को दर्शाता है। सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बाकू में बसे पंजाब के हिंदू खत्री व्यापारियों द्वारा पुनर्निर्मित, यह मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में, बल्कि व्यापारिक नेटवर्क द्वारा समर्थित एक संस्थागत केंद्र के रूप में भी कायम रहा। चौबीस खिड़की रहित कोठरियों से घिरा प्रांगण, मठ और सराय दोनों के रूप में कार्य करता था, जिसमें तपस्वी और व्यापारी समुदाय निवास करते थे, जिन्होंने पवित्र अग्नि परंपराओं को जीवित रखा।

किस ओर जा रही है दुनिया, कौन करेगा इस एआई का इस्तेमाल?

प्रश्न यह कि क्या इस तरह की चुनौतियों का निक्षेपण करने के लिए आज कोई देश, कोई नेता अथवा सरकार है, जो दैवीय राजत्व से नीचे उतरकर सामाजिक अनुबंधों के सहारे आगे बढ़ने का साहस करे? क्या राज्य और उनकी सरकारें इस संदर्भ में कोई व्यवस्था बना सकती हैं? शायद नहीं। दरअसल, यह छद्म वैश्वीकरण और छद्म उदारवाद का दौर है, जिसे हम बनावटीपन के साथ नवविश्ववाद और नवउदारवाद का नाम दे सकते हैं। यहां विशुद्ध (प्योर) कुछ भी नहीं है, सब हाइब्रिड है। सर्वत्र कौन जीतेगा या कौन हारेगा, की विषाक्तता भरी राजनीति का प्रभाव है, जो समृद्ध साझे अनुभवों, विरासतों और हितों से बहुत दूर खड़ी है। फिर तो जो प्रतिस्पर्धा, संघर्ष या युद्ध दिख रहे हैं, उनकी अगुआई ड्रोन, रासायनिक या जैविक हमले ही करेंगे और इन सबके पीछे खड़ी हो सकती है एआई जैसी अदृश्य शक्ति।

(रहीस सिंह)

सनक और अधिनायकत्व के वर्तमान दौर में जब छोटे देश जमींदोज किए जा रहे हों, दुनिया तमाशा देख रही हो और शांति के सिरे पूरी तरह बिखर चुके हों, जिन्हें जोड़ने वाला वैश्विक नेतृत्व भी नदारद हो, तब सवाल यह है कि तेजी से बढ़ते एआई का असली यूजर कौन होगा और उसका मकसद क्या होगा? यह वाकई डराने वाला है। पिछले कुछ दिनों से दुनियाभर के प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर आ रही रिपोर्टों, स्टोरियों और स्तंभों में एक अलग दुनिया दिख रही है। अमेरिका के कई हिस्सों के लोग तकनीक, बाजार और राज्य की व्यवस्था से परे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन बाजार के खिलाड़ी इस प्रतिरोध को 'हिलबिली अपराइजिंग' कहकर मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। क्या इन विशेषताओं के झरोखों में 18वीं-19वीं सदी का वह इतिहास नहीं दिख रहा, जिसने एक तरफ दुनिया को औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद दिया था, वहीं दूसरी तरफ 'सोशल कॉन्ट्रैक्ट' से लेकर 'दास कैपिटल' के जरिये एक ऐसा वर्ग खड़ा कर दिया था, जिसने नई व्यवस्था और नए इतिहास को जन्म दिया? क्या इतिहास अब स्वयं को दोहराने की ओर बढ़ रहा है? या उससे भी अधिक जटिल समय से हमारा सामना होने वाला है? पिछले दिनों प्यू रिसर्च सेंटर का एक सर्वे आया, जिसमें मुख्य रूप से पांच बातें अधिक प्रभावित करने वाली लगीं। पहली, 24 देशों में किए गए सर्वे में अमेरिकी सबसे अधिक निराशावादी दिखे। उनका मानना है कि 'एआई' के प्रभाव सकारात्मक के मुकाबले नकारात्मक अधिक होंगे। दूसरी, अमेरिका में 'एआई' पर बहस अब केवल तकनीकी मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दा बन चुकी है। तीसरी, अमेरिकियों का कहना है कि 'एआई' पहले 'व्हाइट कॉलर' नौकरियां खत्म करेगा, फिर 'ब्लू कॉलर' नौकरियों को। चौथी, यदि इसके कारण दौलत कुछ कंपनियों के हाथ में सिमट गई और बाकी लोग बेरोजगार हुए, तो लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। पांचवीं, 'एआई' लोगों को और भी अकेला बना देगा। इससे 'ट्रांसह्यूमनिज्म' का खतरा भी है, क्योंकि इसके जरिये इन्सान अपनी जैविक सीमाओं से आगे निकल सकता है। सवाल यह है कि अमेरिकियों का यह डर क्या जायज है? शेष दुनिया उतनी चिंतित क्यों नहीं, जितना कि अमेरिका? प्रश्न यह कि क्या इस तरह की चुनौतियों का निक्षेपण करने के लिए आज कोई देश, कोई नेता अथवा सरकार है, जो दैवीय राजत्व से नीचे उतरकर सामाजिक अनुबंधों के सहारे आगे बढ़ने का साहस करे? क्या राज्य और उनकी सरकारें इस संदर्भ में कोई व्यवस्था बना सकती हैं? शायद नहीं। दरअसल, यह छद्म वैश्वीकरण और छद्म उदारवाद का दौर है, जिसे हम बनावटीपन के साथ नवविश्ववाद और नवउदारवाद का नाम दे सकते हैं। यहां विशुद्ध (प्योर) कुछ भी नहीं है, सब हाइब्रिड है। सर्वत्र कौन जीतेगा या कौन हारेगा, की विषाक्तता भरी राजनीति का प्रभाव है, जो समृद्ध साझे अनुभवों, विरासतों और हितों से बहुत दूर खड़ी है। फिर तो जो प्रतिस्पर्धा, संघर्ष या युद्ध दिख रहे हैं, उनकी अगुआई ड्रोन, रासायनिक या जैविक हमले ही करेंगे और इन सबके पीछे खड़ी हो सकती है एआई जैसी अदृश्य शक्ति। क्या तब भी हम सोच सकते हैं कि दुनिया किसी नियम आधारित व्यवस्था से चलेगी? या उस व्यक्ति, देश अथवा बाजार की इकाई से, जिसके पास ताकत नहीं, बल्कि एआई होगा? वैसे नियम आधारित व्यवस्था को तो हम गाजा, कीव और तेहरान के कब्रिस्तानों में दफन होते हुए देख ही चुके हैं। इसलिए, उससे कोई उम्मीद रखना बेकार है। अब चिंता यह है कि नई व्यवस्था और ताकत में मनुष्य कहां खड़ा होगा, क्योंकि लोगों के मस्तिष्कों में अब यह सवाल तैरने लगा है कि जब नौकरियों को बड़े पैमाने पर 'एआई' खा रहा होगा, जब दुनिया भर के डाटा सेंटर लोगों के हिस्से का पानी पी रहे होंगे और फिर जो भ्रम फैलाया जा रहा होगा, वह पहले किसे तोड़ेगा? समाज को या राज्य को अथवा मनुष्य को? पता नहीं, परंतु शिकार मनुष्यता ही होगी, यह तय है। जो भी हो, दुनिया वैश्वीकरण के उस झूठे इश्तिहार के सहारे चलेगी, जो 1990 के दशक में दिमागों के साथ खेल रहा था या फिर उस भ्रम के साथ, जहां कुछ देश संरक्षणवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर अधिनायकवाद को बढ़ाते हुए वैश्विक टकरावों को हवा दे रहे होंगे? लोग भावी बदलावों के बीच अपने लिए एक भरोसा चाहते हैं। परंतु, यह भरोसा दिलाएगा कौन? बाजार, राजनीति या तकनीक? बाजार का चरित्र पहले से ही अदृश्य शक्तियों के हाथ में है, उससे उम्मीद करना बेमानी होगी। अब तो राजनीति का चरित्र भी बाजार तय करने लगा है। और रही बात तकनीक की, तो वह भी बाजार के हाथ में जा चुकी है। तब बचा कौन? एक बात और, 'एआई' बहुत तेजी से बदल रहा है, इसलिए इसे पकड़ पाना मुश्किल है। राजनीति इसके मुकाबले फिसड्डी है। अमेरिका में यह देखने में आया है कि जितने समय में कांग्रेस (अमेरिकी संसद) एक सुनवाई करती है, उतने समय में नया 'एआई' मॉडल आ जाता है। ध्यान रहे कि वर्ष 2030 तक अत्याधुनिक एआई मॉडल विकसित करने के लिए आवश्यक विशाल डाटा सेंटर केवल वर्जीनिया या कैलिफोर्निया तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अमेरिका के अधिकांश क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सर्वर फार्म के रूप में स्थापित हो चुके होंगे। जैसे-सिलिकॉन हार्टलैंड यानी मिशिगन, विस्कॉन्सिन और ओहियो तथा इससे भी आगे बढ़कर दक्षिणी राज्यों, विशेषकर लुसियाना, मिसीसिपी और टेक्सास तक। अमेजन, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसी कंपनियां मिलकर लगभग 750 अरब डॉलर का निवेश कर रही हैं, जबकि अन्य कंपनियां भी अरबों डॉलर लगा रही हैं। एक अनुमान के अनुसार, 2026 से 2030 के बीच दुनियाभर में एआई डाटा सेंटरों पर लगभग तीस खरब डॉलर खर्च होने वाले हैं। इन सेंटरों में खपत होने वाली बिजली करीब 12 गीगावाट के स्तर से इस दशक के अंत में पांच गुना हो जाएगी। तब तो अमेरिकियों का डरना स्वाभाविक है। वे जनरेटरों और कूलिंग सिस्टम के गूंजते शोर और इनकी ओर मुड़ती पानी की धाराओं से डर रहे हैं। फिलहाल, इस समय में जो चिंताएं उभरती दिख रही हैं, वे निराधार तो नहीं हैं। विचार कीजिए कि जब एक नेता किसी दूसरे संप्रभु देश के चुने राष्ट्रपति को इसलिए उठा ले जा सकता है, क्योंकि उसे उस देश का तेल चाहिए। वही नेता एक अन्य देश पर इसलिए हमला कर दे, क्योंकि उसका दोस्त ऐसा चाहता है। छोटे देश जमींदोज कर दिए जाएं और दुनिया तमाशा देखती रहे। यह क्या है? सदी के सबसे खतरनाक कदमों की दस्तक या कुछ और, जो यह बताती है कि सनक, अधिनायकत्व और पोस्ट ट्रुथ के दशकों में शांति के सिरे पूरी तरह बिखर चुके हैं और उन्हें जोड़ने वाला वैश्विक नेतृत्व नदारद है। फिर एआई का असली उपयोगकर्ता कौन होगा और उसका मकसद क्या होगा? यह बात तो डराएगी ही। जो भी हो, यह व्यवस्था, बाजार

दिगर राज्य के गांजा परिवहन करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार

थाना केशकाल जिला कोण्डागाँव पुलिस द्वारा किया गया कार्यवाही

कोण्डागांव। केशकाल पुलिस के द्वारा लगातार अंन्तराज्यीय गांजा तस्करों पर कार्यवाही की जा रही है। मुखबिर के माध्यम से सूचना मिला कि एक सफेद रंग का हुंडई वरना कार क्रमांक यूपी 19 एक्स 8771 में अवैध मादक पदार्थ गांजा छिपा कर उडिसा से रायपुर की ओर जगदलपुर केशकाल के रास्ते से जाने वाले है। उपरोक्त सूचना पर रवाना होकर केशकाल घाटी मोड क्रमांक 09 के पास नाके बंदी कर संदिग्ध वाहन के आने का इंतजार किया मुखबीर के बताये अनुसार हुलिया का संदिग्ध सफेद रंग का हुंडई वरना कार क्रमांक यूपी 19 एक्स 8771 आते दिखायी दिया जिसे रोकवाया गया। सफेद रंग का हुंडई वरना कार क्रमांक यूपी 19 एक्स 8771 में ड्रायवर सीट पर एक व्यक्ति बैठा जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम मोहित शर्मा पिता धर्मवीर सिंह शर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी कासिमपुर खेड़ी तहसील बड़ौत थाना रमाला जिला बागपत (उ.प्र.) का होना बताया। सफेद रंग का हुंडई वरना कार की तलाशी लेने पर कार डिक्की के अंदर भरकर रखा हुआ भूरे रंग के सेलोटेप से पैक किया हुआ 20 पैकेट संदिग्ध मादक पदार्थ गांजा जिसका कुल वजन 102.060 किलोग्राम होना पाया गया आरोपी के द्वारा गांजा जैसा मादक पदार्थ परिवहन करना पाया गया। आरोपी मोहित शर्मा पिता धर्मवीर सिंह शर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी कासिमपुर खेड़ी तहसील बड़ौत थाना रमाला जिला बागपत (उ.प्र.) विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया। जप्त गांजा का बाजार मूल्य 51,03,000 एवं गाड़ी का मूल्य करीब 10,00,000 कुल 61,03,000 है तथा साथ नगद में 1200 जप्त किया गया है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक गुलाब सिंह टण्डन, सहायक उपनिरीक्षक हेमन्त देवांगन, सउनि, रामकृष्ण जैन, प्रआर, राकेश जुरी, आर. मनोहर निषाद, धर्मेन्द्र नेगी, जितेन्द्र माहला, लिलेश्वर ध्रुव, अमित मण्डावी, अजय बघेल, रामुराम नेताम, कैलाश मरकाम, जीएस. कुलदीप एवं साइबर सेल कोंडागांव की अहम भूमिका रही।

अवैध शराब तस्करी पर कोण्डागांव पुलिस की कार्यवाही

कोण्डागांव। पुलिस अधीक्षक पंकज चन्द्रा से जिला कोंडागांव में अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगाने एवं कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त है। अवैध शराब तस्करी पर अकुंश लगाने लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाता है। इसी दौरान 15 जूलाई को मुखबीर के माध्यम से सूचना मिला कि एक ग्रे रंग का मारूति स्वीफ्ट कार क्र. सीजी 09 जेए 1140 में अवैध शराब हेतु रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रहे है, की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ उपाध्याय के नेतृत्व में थाना कोण्डागांव एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर नया बस स्टैण्ड के आगे बायपास एनएच 30 मेन रोड तिराहा चिखलपुटी कोण्डागांव के पास पहुंचकर नाकाबंदी किया गया। संदिग्ध ग्रे रंग का मारूति स्वीफ्ट कार क्र. सीजी 09 जेए 1140 आने पर उसे रोकने का प्रयास किया गया नही रोकने पर स्कार्पियो वाहन कमांक को सामने अड़ाकर रोकने पर कार चालक के द्वारा अपने वाहन को लापरवाही एवं तेज चलाकर स्कार्पियो को ठोकर मारकर भागने का प्रयास कर रहा था। जिसे पुलिस बल द्वारा रोका गया। संदिग्ध कार को चेक करने पर कार के अंदर कुल 32 पेटी में अग्रेजी शराब गोवा व्हीहस्की कुल मात्रा 285.284 बल्क लीटर मिला जिसे जप्त किया गया एवं आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट के तहत् अपराध पाये जाने से थाना कोतवाली कोण्डागांव में अपराध कमांक 222/2026 धारा 281 बीएनएस 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् अपराध दर्ज किया गया तथा आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ उपाध्याय, सहा.उप निरी. पिताम्बर कठार, आरक्षक सुखीराम राजपूत, सायबर सेल से प्रआर. अजय बघेल, आर. संतोष कोडोपी, आर. बिरजू सोरी, आर. बिजु यादव, आर. चंदन यादव का विशेष योगदान रहा है।

सेजेस केशकाल की शिक्षिका संध्या श्रीवास्तव को मिला स्व. हरिवंश मिश्रा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान

केशकाल। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट, नवाचारी एवं प्रेरणादायी कार्यों के लिए दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पीएमश्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय केशकाल की अंग्रेज़ी व्याख्याता संध्या श्रीवास्तव को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्व. हरिवंश मिश्रा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान-2026 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें रायपुर में राष्ट्रीय शिक्षा अंजोर भारत द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। जानकारी के अनुसार, इस वर्ष देशभर से प्राप्त लगभग 700 आवेदनों के मूल्यांकन एवं सत्यापन के बाद 240 शिक्षकों का चयन किया गया, जिन्हें विभिन्न राज्यों एवं जिलों से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह रायपुर के शांति नगर स्थित विमलतारा, मधु पिल्ले चौक में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि हरिभूमि समूह के प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद् एवं समाजसेवी संजय अग्रवाल ने की, जबकि डॉ. चित्तरंजन कर एवं डॉ. पूर्णानंद मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बता दें कि श्रीवास्तव अब तक विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए 20 से अधिक पुस्तकें एवं डिजिटल शिक्षण सामग्री तैयार कर चुकी हैं। उनका योगदान केवल कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि वे शिक्षक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्माण, पुस्तक लेखन, नवाचारी शिक्षण पद्धतियों के विकास तथा शिक्षा में एआई के प्रभावी समावेशन पर भी निरंतर कार्य कर रही हैं। बइस राष्ट्रीय सम्मान से विद्यालय परिवार, विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षा जगत में हर्ष का वातावरण है।
सभी ने संध्या श्रीवास्तव को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दी हैं। उनके इस सम्मान ने केशकाल, कोंडागांव और पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है।

सुरक्षा और विश्वास का सेतु : आईटीबीपी ने जाटलूर नाला पर बनाया 250 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज

सिविक एक्शन प्रोग्राम में साइकिल एवं दैनिक उपयोग की सामग्री वितरित

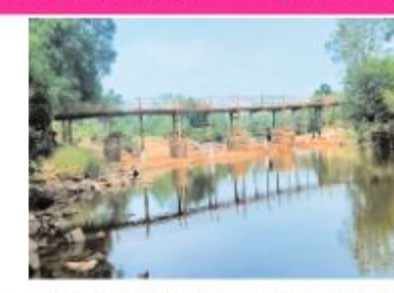

नारायणपुर। पूर्व में नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय नागरिकों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने की दिशा में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) की 38वीं वाहिनी ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। जाटलूर नाला पर निर्मित 250 फीट लंबे लकड़ी के फुट सस्पेंशन ब्रिज का लोकार्पण केंद्रीय सीमांत मुख्यालय के महानिरीक्षक श्री अजय पाल सिंह ने किया। यह पुल क्षेत्र के ग्रामीणों, विद्यार्थियों एवं सुरक्षा बलों के लिए वर्षभर सुरक्षित और सुगम आवागमन का माध्यम बनेगा। लगभग 250 फीट लंबे, 5 फीट चौड़े और 15 फीट ऊँचे इस सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण आईटीबीपी के जवानों तथा स्थानीय ग्रामीणों के संयुक्त श्रमदान एवं स्थानीय संसाधनों के उपयोग से किया गया है। बरसात के दौरान जाटलूर नाला उफान पर होने से आवागमन बाधित हो जाता था, जिससे ग्रामीणों और स्कूली विद्यार्थियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पुल के निर्माण से अब इस समस्या का स्थायी समाधान हो गया है और आवागमन अधिक सुरक्षित एवं निर्बाध हो सकेगा। लोकार्पण समारोह में कमांडेंट श्री राजीव गुप्ता (45वीं वाहिनी), श्री अभिषेक सूद (29वीं वाहिनी), द्वितीय कमान श्री अशोक कुमार सिंह (38वीं वाहिनी), श्री संजय कुमार (53वीं वाहिनी) सहित केंद्रीय सीमांत मुख्यालय एवं आईटीबीपी की विभिन्न वाहिनियों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण, शिक्षक एवं छात्र-छात्राओं ने भी सहभागिता की। इस अवसर पर आईटीबीपी द्वारा संचालित सिविक एक्शन प्रोग्राम (सीएपी) के तहत स्कूली विद्यार्थियों एवं जरूरतमंद ग्रामीणों को साइकिलों का वितरण किया गया। साथ ही स्वरोजगार, कौशल विकास तथा केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुल निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों एवं जवानों को महानिरीक्षक श्री अजय पाल सिंह ने प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस नव-निर्मित सस्पेंशन ब्रिज का नाम नक्सल विरोधी अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद अमोल माधव राव महस्के की स्मृति में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पुल शहीद के अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक रहेगा तथा आने वाली पीढ़ियों और सुरक्षा बलों के जवानों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा।

सुदूर वनांचल में जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी की जनचौपाल

हिरोली, कड़मपाल और मदाडी के दौरे में ग्रामीणों से किया सीधा संवाद; मौके पर ही समस्याओं का समाधान, दिव्यांगों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों को मिली त्वरित राहत

किरंदुल। जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी ने जनप्रतिनिधियों के साथ जिले के सुदूर वनांचल स्थित ग्राम पंचायत हिरोली, कड़मपाल एवं मदाडी का व्यापक दौरा कर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। उन्होंने गांव-गांव पहुंचकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया, ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं तथा कई मामलों में मौके पर ही समाधान सुनिश्चित कर प्रशासनिक संवेदनशीलता और त्वरित कार्यवाही का उदाहरण प्रस्तुत किया। दौरे के दौरान मुड़ामी ने स्पष्ट कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य अंतिम छोर पर खड़े पात्र हितग्राही तक बिना किसी बाधा के लाभ पहुंचाना है।

दिव्यांगजनों की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई

ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कई दिव्यांगजनों ने बताया कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र नहीं बनने के कारण वे विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर निर्देश किया गया। स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग की टीम ने बिना विलंब दिव्यांगजनों को जिला अस्पताल पहुंचाकर उनके दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

दिव्यांग बालक की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई

दौरे के दौरान एक दिव्यांग बालक विनय कुमार की शिक्षा का विषय सामने आने पर मुड़ामी ने तत्काल संवेदनशीलता दिखाते हुए उसका प्रवेश सक्षम विद्यालय, जावंगा में सुनिश्चित कराने को कहा शिक्षा विभाग ने तत्काल दिव्यांग बालक सक्षम विद्यालय जावंगा के दाखिला करवाया।

बुजुर्ग महिला का घर पहुंचकर कराया गया ई-केवाईसी

ग्राम पंचायत कड़मपाल में आग से झुलसकर चलने-फिरने में असमर्थ एक बुजुर्ग महिला बोदे से मुलाकात के दौरान यह जानकारी मिली कि ई-केवाईसी नहीं होने के कारण वे महतारी वंदन योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित थीं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर उनका ई-केवाईसी पूर्ण कराया। कुछ ही समय में प्रक्रिया पूरी होने से महिला के लिए शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का रास्ता खुल गया।

ग्रामीणों की मांगों पर प्राथमिकता से कार्रवाई

दौरे के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, राशन एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं और मांगों से जिला पंचायत अध्यक्ष को अवगत कराया।

मुड़ामी ने सभी विषयों की गंभीरता से समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रत्येक समस्या का प्राथमिकता समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविंद कुंजाम, जनपद पंचायत अध्यक्ष सुकालू मुंडामी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सुमित भदौरिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सोरी, सरपंच राजू, क्षेत्र के विभिन्न सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

किरंदुल में श्रद्धा और उल्लास के साथ निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, हजारों भक्तों ने खींचा रथ

किरंदुल। लौहनगरी किरंदुल में श्री जगन्नाथ सेवा समिति और ऊकल समाज के संयुक्त तत्वावधान में प्रति वर्ष की भाँति इस वर्ष भी भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। श्री जगन्नाथ मंदिर से दोपहर में विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना के बाद महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का रथ निकाला गया।रथ निकलते ही जय जगन्नाथ के नारों से पुरा नगर गुंजायमान हो उठा।पुरी और ओडिशा से आए पांडाओं ने पारंपरिक रीति से पूजन संपन्न कराया।रथ संचालन श्री राघव मंदिर प्रांगण से शुरू हुआ। इस दौरान जगन्नाथ परंपरा की सबसे पवित्र रस्म छेरा पहरा एनएमडीसी किरंदुल के अधिशासी निदेशक खींद्र नारायण ने सोने की झाड़ू से रथ की सफाई कर निभाई।रथ यात्रा के मार्ग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्त रथ को छूकर आशीर्वाद लेने और भगवान के दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे।डीजे और भजनों की धुन पर युवा झूमते नजर आए।यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रात 8 बजे फुटबॉल ग्राउंड स्थित ऊकल समाज भवन के गुंडिचा मंदिर यानी मौसी के घर पहुंचकर संपन्न हुई।समापन के बाद सभी भक्तों को खिचड़ी प्रसाद वितरित किया गया। इस पावन अवसर पर जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष आर. सी. नाहक, ऊकल समाज के अध्यक्ष अविनाश स्वाई, देवराज लेंका, दीपक मोहंती, ब्रजेश मिश्रा सहित समिति के सदस्य और हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहें। आयोजकों ने बताया कि शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से यात्रा संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन एवम भक्तों का विशेष सहयोग रहा।

सुदूर वनांचल में जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी की जनचौपाल

दंतेवाड़ा। जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी ने जनप्रतिनिधियों के साथ जिले के सुदूर वनांचल स्थित ग्राम पंचायत हिरोली, कड़मपाल एवं मदाडी का व्यापक दौरा कर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। उन्होंने गांव-गांव पहुंचकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया, ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं तथा कई मामलों में मौके पर ही समाधान सुनिश्चित कर प्रशासनिक संवेदनशीलता और त्वरित कार्यवाही का उदाहरण प्रस्तुत किया। दौरे के दौरान मुड़ामी ने स्पष्ट कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य अंतिम छोर पर खड़े पात्र हितग्राही तक बिना किसी बाधा के लाभ पहुंचाना है। ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कई दिव्यांगजनों ने बताया कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण वे विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।

नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों की ली समीक्षा बैठक

ट्रस्ट बिल्डिंग (विश्वास निर्माण) को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के दिए निर्देश

सीएम हेल्पलाइन एवं राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल में प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

नारायणपुर। जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक लेकर थाना क्षेत्रों की कानून-व्यवस्था, नक्सल गतिविधियों एवं पुलिसिंग व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक थाना प्रभारी से उनके थाना क्षेत्र की कानून-व्यवस्था, नक्सल गतिविधियों, स्थानीय राजनीतिक समीकरण, सामाजिक संगठनों की सक्रियता, संवेदनशील क्षेत्रों, जनसमस्याओं तथा पुलिस के समक्ष आने वाली चुनौतियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही थाना क्षेत्रों में संचालित पुलिस गतिविधियों, अपराध नियंत्रण, जनसंपर्क, लंबित अपराध एवं शिकायतों तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी विस्तार से समीक्षा की। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल ने कहा कि नारायणपुर जिला वर्तमान में नक्सल समस्या के समाप्ति उपरांत संक्रमणकाल से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस की प्राथमिकता केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि आम जनता के साथ विश्वास का मजबूत संबंध स्थापित करना भी है।
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में ट्रस्ट बिल्डिंग (विश्वास निर्माण) को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आमजन से निरंतर संवाद स्थापित करें, नियमित ग्राम भ्रमण करें तथा उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, प्रबुद्ध नागरिकों एवं युवाओं के साथ सतत संपर्क बनाए रखने, थाना क्षेत्र की प्रत्येक गतिविधि पर सतर्क निगरानी रखने तथा सक्रिय एवं प्रभावी पुलिसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक पटेल ने सभी थाना प्रभारियों को आईआरएडी, ई-डीएआर एवं सीसीटीएनएस पोर्टलों में शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी पोर्टलों में दर्ज जानकारी की गुणवत्ता एवं अद्यतन स्थिति बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त , पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को लंबित प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण, अनुशासन, पारदर्शिता तथा जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

भारी बारिश में मौसमी बीमारियों से निपटने स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आपातकालीन नंबर

बिलासपुर। भारी बारिश के मद्देनजर मौसमी बीमारियों की रोकथाम और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने स्वास्थ्य विभाग ने आपातकालीन संपर्क नंबर जारी किए हैं। जिले में किसी भी विशेष आपातकालीन स्थिति अथवा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता पर नागरिक जिला एवं विकासखंड स्तर की कॉम्बेट टीम से संपर्क कर सकते हैं। जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार तिवारी से 8770664365 पर संपर्क किया जा सकता है। बिलासपुर शहर के लिए खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. रक्षित जोगी का मोबाइल नंबर 9009727934 जारी किया गया है। इसी प्रकार बिल्हा विकासखंड के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्रीकेश गुप्ता (9009731426), कोटा के डॉ. निखिलेश गुप्ता (9770146540), मस्तूरी के डॉ. अनिल कुमार (9827505957) तथा तखतपुर के डॉ. उमेश साहू (9407728300) से संपर्क किया जा सकता है। शहरी स्तर पर शहरी कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. टार्जन आदिले का मोबाइल नंबर 7241133198 तथा जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट श्री पंकज सिंह का मोबाइल नंबर 7587038622 जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान बुखार, उल्टी-दस्त अथवा अन्य मौसमी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें और समय पर उपचार लें।

तेज रफ्तार पिकअप पलटी, दो महिला मजदूरों की मौत, दर्जनों घायल

बलरामपुर। जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो महिला मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य घायल हो गईं। हादसा जरगिमा-जुड़वानी गांव के पास उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। जानकारी के अनुसार, पिकअप वाहन में करीब 20 से 25 महिला मजदूर सवार थीं। सभी मजदूर परेवा गांव में धान रोपाई का काम करने के बाद अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे में दो महिला मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गईं। घायलों में तीन महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया गया है। अन्य घायलों का उपचार शंकरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। घटना की सूचना मिलते ही शंकरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे की वजह वाहन की तेज रफ्तार और अनियंत्रित होना मानी जा रही है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

जनदर्शन में हंगामा, लोजपा नेता और खाद्य निरीक्षक के बीच तीखी बहस

कोरबा । जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के जिला अध्यक्ष राजकुमार दुबे और खाद्य निरीक्षक संतोष कंवर के बीच तीखी बहस होने का मामला शिकायत पत्र के जरिए प्रकाश में आया है। लोजपा जिला अध्यक्ष ने खाद्य निरीक्षक पर जनदर्शन जैसे जन-कल्याणकारी मंच पर शासकीय अधिकारियों को गुमराह करने और विरोध करने पर सरेआम फर्जी मामलों सहित एससी/एसटी एक्ट में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. मामले को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, 13 जुलाई 2026 को आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में जिला पंचायत सीईओ, आईएएस आम जनता की शिकायतें सुन रहे थे। इसी दौरान लोजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार दुबे खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम से जुड़ी गंभीर शिकायतों को लेकर उपस्थित हुए थे। आरोप है कि जिला खाद्य अधिकारी स्वयं उपस्थित न होकर अपनी जगह खाद्य निरीक्षक संतोष कंवर को भेजे थे। जब सीईओ महोदय ने आवेदन पर जानकारी मांगी, तो खाद्य निरीक्षक संतोष कंवर द्वारा भ्रामक और गलत जानकारी दी जाने लगी। जब राजकुमार दुबे ने इस पर आपत्ति जताई, तो खाद्य निरीक्षक अपना आपा खो बैठे और जनदर्शन परिसर में ही सबके सामने उन्हें फर्जी मुकदमों और एससी/एसटी एक्ट के तहत जेल भिजवाने की खुली धमकी दे डाली। कलेक्टर को सौंपे गए पत्र में राजकुमार दुबे ने विभाग में चल रहे भाई-भतीजावाद पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि खाद्य निरीक्षक संतोष कंवर, जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम कंवर के करीबी रिश्तेदार हैं। इसी संरक्षण के कारण उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों और कटघोरा क्षेत्र की राशन दुकानों (पीडीएस) में भारी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार चरम पर है।

भारी बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दिए राहत एवं बचाव के निर्देश

■ कच्चे मकान क्षतिग्रस्त होने पर आरबीसी 6(4) के तहत तत्काल प्रकरण बनाकर राहत दिलाने कहा

बिलासपुर। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारी बारिश के कारण जिले में कई नदी-नाले उफान पर हैं और निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति निर्मित हुई है। कुछ स्थानों पर कच्चे मकानों के क्षतिग्रस्त होने की भी जानकारी मिली है। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने राजस्व और निगम अमले को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचकर स्थिति का सर्वे करें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके आरबीसी 6(4) के तहत तत्काल प्रकरण तैयार किए जाएं, ताकि नियमानुसार पात्र प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे और राहत संबंधी कार्रवाई में किसी भी प्रकार की देरी न हो। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों और मैदानी अमले को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नदी-नालों के जलस्तर, जलभराव वाले क्षेत्रों और निचली बस्तियों की स्थिति पर विशेष नजर रखी जाए। आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई तत्काल की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दी जाए और राहत एवं बचाव कार्य में सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आम नागरिकों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान नदी, नाले, रपटों और जलभराव वाले स्थानों के पास जाने से बचें। उफनते नदी-नालों को पार करने का प्रयास न करें। बच्चों को विशेष रूप से ऐसे स्थानों से दूर रखें। पुल-पुलियों अथवा रपटों पर पानी बहने की स्थिति में किसी भी प्रकार का जोखिम न लें। जर्जर अथवा क्षतिग्रस्त मकानों में निवास न करें। यदि किसी परिवार का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है अथवा किसी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति है, तो तत्काल स्थानीय प्रशासन अथवा राजस्व अमले को सूचना दें। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कर नियमानुसार राहत की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा है कि भारी बारिश के दौरान आमजन की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और आवश्यकता के अनुसार राहत एवं बचाव के सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ की 19 नदियों के संरक्षण को बनेगी कमेटी.....

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थल सूखने का कारण जानने और इन स्थलों को तलाशने के लिए राज्य सरकार द्वारा कमेटी बनाई जाएगी। साथ ही प्रदेश की 19 नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह कमेटी काम करेगी। चीफ सेक्रेटरी ने सभी चयनित मुख्य नदियों के उद्गम स्थल को चिन्हांकित कर सुरक्षित करने की बात बुधवार को हाईकोर्ट में कही। उन्होंने बताया कि विषय विशेषज्ञों की एक टीम बनाकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नदियों को संरक्षित किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सभी नदियों और उनके उद्गम स्थल को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। बता दें, कि रिकॉर्ड में यह नदियां और उनके उद्गम स्थल फिलहाल नाले के रूप में दर्ज हैं। शासन द्वारा प्रस्तुत जवाब में कहा गया कि 6 नदियों महानदी, हसदेव, तांदूला, पैरी, केलो, मांड के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद शासन ने कमेटी में इतिहासकार, लेखक, पर्यावरणविद को भी शामिल किया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अरपा में सालभर पानी की योजना के साथ प्रदेश की 11 प्रमुख नदियों के रिवाइवल की योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार ने इस बात पर भी सहमति जताई कि नई कमेटी गठित कर नदियों के स्रोतों की पहचान और संरचना सुनिश्चित की जाएगी। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान बताया कि सरकार नदियों के उदगम स्थल के संरक्षण की बात तो कर रही है लेकिन इसके बाद आगे 2 किलोमीटर क्षेत्र तक के प्राकृतिक प्रवाह पर ध्यान नहीं है। इन क्षेत्रों में कब्जा करते हुए खेती हो रही है। इसे भी संरक्षित करना होगा। कहीं कोई निजी जमीन है तो उसका अधिग्रहण सरकार को करना होगा, कब्जे हटाने होंगे। इसके बाद ही नदियों का प्रवाह बेहतर हो सकेगा। हाईकोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए सरकार को इस तरफ ध्यान देने कहा है। ध्यान रहे कि छत्तीसगढ़ में 19 छोटी-बड़ी नदियों का उद्?गम है जिन पर कब्जा हो चुका है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थल आखिर क्यों सूख रहे हैं, यह जानने और इन स्थलों को तलाशना सबसे जरूरी है।

एसईसीएल कुसमुंडा मेगा परियोजना पर प्रधानमंत्री मोदी की सीधी नजर..

कोरबा। देश की सबसे बड़ी कोयला परियोजनाओं में शामिल एसईसीएल की कुसमुंडा मेगा परियोजना पर अब प्रधानमंत्री कार्यालय की सीधी नजर है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के प्रतिनिधिमंडल ने कुसमुंडा परियोजना का दौरा कर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्यों की जमीनी समीक्षा की। इस दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के साथ ही अधिकारियों को लंबित कार्य तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रतिनिधिमंडल में पीएमजी के लीडदूपॉलिसी एवं पीएमओ एंगेजमेंट्स आनंद शर्मा, आकृति लाल, अंजलि गुप्ता, कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत, एडीएम देवेंद्र पटेल, एसडीएम कटघोरा सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। कुसमुंडा क्षेत्र के महाप्रबंधक सचिन टी. पाटिल ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए परियोजना की प्रगति और पुनर्वास कार्यों की जानकारी दी। समीक्षा बैठक में अधिकारियों के समक्ष भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति, प्रभावित भू-स्वामियों और पात्र किरायेदारों को दिए गए मुआवजे, रोजगार, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्यों तथा लंबित मामलों पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि परियोजना प्रभावित परिवारों को सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने खमरिया पुनर्वास स्थल का निरीक्षण किया, जहां पाली और खोदरी गांव के विस्थापित परिवारों को बसाने की तैयारी चल रही है। अधिकारियों ने आवास, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया तथा शेष निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद टीम ने 14 नंबर डंप आर एंड आर साइट का भी निरीक्षण किया, जहां जटराज गांव के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पुनर्वास कार्यों की प्रगति का आकलन किया और परियोजना क्षेत्र में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। दौरे के दौरान एसईसीएल के महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग) रितेश सोबती सहित कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

लगातार बारिश के मद्देनजर कलेक्टर संजय ने अधिकारियों को दिए फील्ड में रहने के निर्देश..

■ आज की सभी बैठकें निरस्त, जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश

बिलासपुर। जिले में लगातार हो रही बारिश और कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज की सभी बैठकें निरस्त कर दी हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को फील्ड में रहकर स्थिति की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि कई स्थानों से 3 से 4 फीट तक पानी भरने की सूचना प्राप्त हो रही है। ऐसे क्षेत्रों में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए।

नगर निगम और जनपद पंचायत के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर स्थिति का जायजा लें। उन्होंने संबंधित वर्क्स विभाग के अधिकारियों को सड़क, नदी और नालों की स्थिति का निरीक्षण करने तथा पानी के बहाव का आकलन करने के निर्देश दिए। जहां बैरिकेडिंग अथवा अन्य स्थानीय व्यवस्थाओं की आवश्यकता हो, वहां तत्काल आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि लगातार बारिश की संभावना को देखते हुए सभी अधिकारी जरूरतमंद लोगों के संपर्क में रहें और उन्हें हरसंभव सहयोग प्रदान करें। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी लगातार संपर्क और समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

बिलासपुर में लगातार बारिश के बाद जनजीवन को सामान्य बनाने हेतु अमर अग्रवाल ने दिए निर्देश

बिलासपुर। बिलासपुर में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस चुनौतीपूर्ण समय में बिलासपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने विधानसभा सत्र की व्यस्तताओं के बीच स्थिति का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ मिलकर राहत कार्यों को गति प्रदान की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और उन्हें राहत पहुँचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राहत और बचाव कार्यों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से श्री अग्रवाल ने एक विशेष 'टास्क फोर्स' को निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जलभराव वाले क्षेत्रों में त्वरित जलनिकासी, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति और बिजली सेवाओं की बहाली के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। जनस्वास्थ्य की दृष्टि से उन्होंने सिम्स और जिला अस्पताल को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी मौसमी बीमारी की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त, बारिश के कारण जिन परिवारों के कच्चे मकानों को नुकसान पहुँचा है, उन्हें राहत प्रदान करने हेतु आरबीसी 6(4) के तहत तत्काल मुआवज़ा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा और उनके आवागमन को लेकर भी उन्होंने विशेष सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने सभी पार्षदों और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहकर नागरिकों की हर संभव सहायता करें। अमर अग्रवाल ने शहरवासियों से सुरक्षित रहने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के आपसी सहयोग से शहर की स्थिति जल्द ही पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। दोपहर बाद बारिश थमने के साथ ही प्रशासन अब प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को सुचारु बनाने के कार्य में पूरी तत्परता से जुटा हुआ है।

लगातार हो रही बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का कलेक्टर-एसएसपी ने किया गया निरीक्षण..

■ जल भराव से निपटने बनेगा स्थायी एक्शन प्लान

■ बाढ़ पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश

बिलासपुर। लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने पुलिस, प्रशासनिक एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ शहर के जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विजयापुरम, बंधवापारा, तोरवा, रेलवे कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों का जायजा लेकर जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों से चर्चा कर उन्हें दिलासा दिया कि प्रशासन इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ है। उन्हें हर संभव सुरक्षा और सहायता दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर के सभी नालों और नालियों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि वर्षा का पानी बिना किसी बाधा के निकल सके। उन्होंने कहा कि जहां आवश्यकता हो, वहां नालों का चौड़ीकरण कराया जाए तथा नालों के मोड़ों पर जल निकासी में बाधा बन रहे अतिक्रमणों को प्राथमिकता के आधार पर हटाने की कार्रवाई की जाए। कलेक्टर श्री

अग्रवाल ने जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल निकासी तंत्र का वैज्ञानिक अध्ययन कर ऐसे उपाय किए जाएं, जिससे भविष्य में शहर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो और नागरिकों को राहत मिल सके। निरीक्षण के दौरान बंधवापारा क्षेत्र में जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने वहां निवासरत लगभग 55 परिवारों को एहतियातन सेंट्रल लाइब्रेरी के समीप स्थित सामुदायिक भवन में आज रात सुरक्षित रूप से शिफ्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए भोजन, पेयजल, बिजली, शौचालय सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी रखें। नगर निगम, राजस्व, पुलिस तथा अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखें। उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक और पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बारिश के मौसम के लिए खाने-पीने से जुड़ी गाइडलाइंस

आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान कहा गया है, जो हमारे रहन-सहन और खाने-पीने के तरीके के बारे में बताता है। अब बारिश का सीजन शुरू हो चुका है तो इस मौसम में सभी को खास देखभाल की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉनसून में इम्युनिटी कमजोर हो जाती है और वात दोष भी बढ़ जाता है, जिससे वायरल बुखार, फूड प्वाइजनिंग और इन्फेक्शन का जोखिम ज्यादा रहता है। इसे देखते हुए आज हम आपको बताएंगे आयुर्वेद के मुताबिक मॉनसून में क्या खाया जाना चाहिए और किन चीजों से सख्त परहेज करना चाहिए। आयुर्वेद बरसात में सादा, गर्म और आसानी से पचने वाले खाने को डाइट में शामिल करने की बात करता है, इसके लिए कई चीजों से परहेज भी किया जाना जरूरी है। आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहती हैं आयुर्वेदिक गाइडलाइंस:

क्या खाना चाहिए?

आयुर्वेद में बारिश के मौसम में पुराने अनाज जैसे- चावल, गेहूं और जौ खाने की बात कही गई है। मूंग की दाल खाना फायदेमंद बताया गया है क्योंकि यह तीनों दोषों- वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने के लिए जानी जाती है। वहीं, यह दाल ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी पेट से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में भी मददगार है। आयुर्वेद कहता है कि मॉनसून में पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है और इस समस्या से निपटने के लिए खाने में उबली हुई सब्जियों को ही शामिल किया जाना चाहिए। उबला और हल्का खाना सबसे बेस्ट माना गया है। घी और तेल जैसी चिकनाई वाली चीजें वात दोष को शांत कर सकती हैं। खट्टी, नमकीन और तीखी चीजों को खाना भी इस मौसम में असरदार बताया गया है।

क्या नहीं खाना चाहिए?

हरी पत्तेदार सब्जियां बरसात में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इस मौसम में पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरिया और कीड़े जल्दी पनपते हैं। दूध और दूध से बनी चीजों से सख्त परहेज करें। इनके सेवन से कफ और पित्त दोष बढ़ता है। फर्मेन्टड चीजो को भी कम से कम शामिल करें, ये पेट से जुड़ी दिक्कतों को बढ़ाकर पित्त दोष अशांत करती हैं। डीप फ्राइड और जंक फूड्स कफ दोष बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस मौसम में कच्ची सलाद खाने से भी बचना चाहिए, इनमें भी बैक्टीरिया और वायरस का खतरा रहता है।

होममेड कंडीशनर बनाने का तरीका

बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने के लिए लोग कई कोशिश करते हैं, कुछ लोग तो बालों को खूबसूरत बनाने के लिए महंगे प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं. इनमें शैंपू, सीरम, कंडीशनर आदि चीजे शामिल होती है, लेकिन अब आप घर बैठे हेयर कंडीशनर बना सकते हैं. इससे आपका खर्च कम होगा और बाल भी मजबूत बनेंगे. घर पर हेयर कंडीशनर बनाना बहुत आसान होता है. आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका क्या है.

घर पर बनाएं हेयर कंडीशनर

घर पर हेयर कंडीशनर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कटोरी में दो चम्मच शहद, दो चम्मच एलोवेरा जेल और चार चम्मच जैतून का तेल लेकर इन तीनो को अच्छे तरीके से मिलाकर पेस्ट तैयार करना होगा. अगर आप चाहे, तो इसमे थोड़ा पानी का इस्तेमाल भी कर सकते है. जब यह पेस्ट तैयार हो जाए, तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए एक तरफ रख दे, फिर किसी बोतल मे भरकर आप कुछ हफ्तो तक इसका इस्तेमाल कर सकते है.

हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल

हेयर कंडीशनर को अपने बालो पर लगाने से पहले आपको अपने बालो को अच्छी तरह शैंपू से धोना होगा. इसके बाद हेयर ब्रश या उंगलियो की मदद से आपको इस होममेड कंडीशनर को अपने बालों पर 20 मिनट के लिए अच्छी तरह लगाकर रखना होगा. 20 मिनट के बाद आप अपने बालों को माइल्ड शैंपू की मदद से धो ले. आप इस होममेड कंडीशनर का एक हफ्ते मे दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं.

होममेड कंडीशनर के फायदे

इस होममेड कंडीशनर को अगर आप एक हफ्ते मे दो बार इस्तेमाल करते है, तो इससे आपके बालो का झड़ना बंद होगा और बाल खूबसूरत बनेंगे. शहद और एलोवेरा जेल मे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है, जो बालो को मजबूत बनाने मे मदद करता है और उन्हें मॉइस्चराइज रखता है. आप अगर चाहे तो इस कंडीशनर मे गुलाब जल का इस्तेमाल भी कर सकते है. इस होममेड कंडीशनर का इस्तेमाल करने से बाल मुलायम तो होंगे ही साथ ही बालो को नमी मिलेगी और रूखापन दूर होगा.

पैच टेस्ट जरूर करें

ध्यान रहे किसी भी हेयर कंडीशनर को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें इससे बालो को नुकसान पहुंच सकता है और बाल सफेद होने लगते हैं. इस होममेड कंडीशनर का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, क्योंकि कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, जिस वजह से बाल और झड़ने लगते है. अगर ऐसा होता है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले.

ट्रेडिशनल ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल

बिना सैलून गए बनाएं ये ट्रेडिशनल ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल

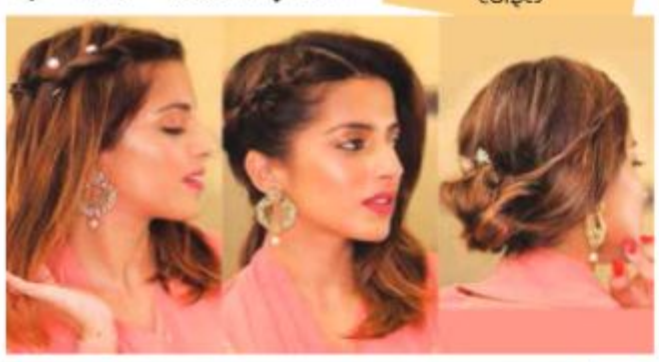

1. गोटा पट्टी ब्रेड – अगर आप सिंपल चोटी बना रही है, तो उसमे थोड़ा ट्रेडिशनल टच लाना बहुत आसान है. बस एक खूबसूरत सी गोटा पट्टी ले और उसे अपनी चोटी के साथ हल्के-हल्के लपेट ले. इससे आपकी चोटी बिल्कुल फैंसी और फेस्टिव दिखेगी. साथ ही कपड़ो के साथ मैचिंग गोटा पट्टी का यूज करे. बालो मे थोड़ा हेयर सीरम लगाकर चोटी बनाएं ताकि बाल फ्रिजी न दिखे .यह हेयरस्टाइल साड़ी, सूट या लहंगे सभी के साथ परफेक्ट लगता है.

2. ओपन हेयर विद साइड ब्रेड – अगर आप बालो को खुला रखना पसंद करती है, लेकिन कुछ नया भी चाहती हैं, तो यह हेयरस्टाइल आपके लिए है. बालो को अच्छे से सुलझाकर सामने की एक साइड से एक छोटी ब्रेड बनाएं और पीछे की तरफ टक करें बाकी बालों को खुला छोड़ दे. हल्के वेव्स या कर्लिंग आयरन से बालो मे कर्ल्स डाले. साथ ही सामने से कुछ बाल छोड़ें, जिससे चेहरा और भी प्यारा दिखेगा. यह स्टाइल एलिगेंट और मॉडर्न है.

3. फ्लावर बन – अगर आप बन हेयरस्टाइल पसंद करती हैं, तो थोड़ा ट्रेडिशनल टच लाइए. एक स्लीक या मेसी बन बनाकर उसमे गजरा, गुलाब के फूल या आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाएं .बालो मे पहले सीरम या क्रीम लगाएं जिससे हेयर बन स्मूथ बने फिर बन बनाने के बाद उसे पिन्स से अच्छे से सेट करें. अब इसमे फूल लगाने से आपका लुक ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल लगेगा.

4. मेसी ब्रेड – अगर आपके बाल पतले है, तो मेसी ब्रेड एक बेस्ट चॉइस है. यह न सिर्फ आसान है, बल्कि बालो को ज्यादा दिखाने मे भी मदद करता है. इसे बनाने के लिए पहले हल्का बैक कॉम्ब करें, जिससे वॉल्यूम बने फिर एक ढीली चोटी बनाएं और उसे हल्के-हल्के खींचें ताकि वो मेसी लुक दे.

बच्चों की सही ग्रोथ के लिए विटामिन बहुत जरूरी

बच्चों की सही ग्रोथ और मजबूत इम्यूनिटी के लिए विटामिन बहुत जरूरी होते हैं। अगर शरीर में किसी विटामिन की कमी हो जाए, तो कुछ खास लक्षण दिखने लगते हैं। इन संकेतों को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है।

विटामिन ए बच्चों की आंखों, इम्युनिटी और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी होने पर बच्चे को रात में कम दिखाई देना शुरू हो सकता है। आंखों में खुजली, सूखापन या बार-बार आंखें मलना भी इसका संकेत हो सकता है। ऐसे बच्चे अक्सर जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते हैं और उनकी भूख भी कम हो सकती है।

विटामिन बी1 शरीर को एनर्जी देने और दिमाग को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर बच्चा चिड़चिड़ा रहने लगता है और उसे हर समय थकान महसूस हो सकती है। कई बच्चों की भूख कम हो जाती है और वे पढ़ाई या खेल में ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ मामलों में नसों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिससे हाथ-पैरों में कमजोरी महसूस हो सकती है। अगर बच्चा अचानक सुस्त रहने लगे, तो डॉक्टर से सलाह ले। विटामिन बी2 की कमी का असर सबसे पहले त्वचा और मुंह पर दिखाई देता है। बच्चे के होंठ बार-बार फटने लगते हैं या मुंह के कोनों पर दरारें पड़ सकती हैं। मुंह में छाले होना, त्वचा पर रैशेज आना और आंखों का लाल या पानी भरा दिखना भी इसके संकेत हैं। इसके अलावा, बच्चे की ग्रोथ धीमी हो सकती है। यदि ये लक्षण लगातार बने रहें, तो बच्चे की डाइट की जांच करवानी चाहिए। विटामिन बी6 दिमाग, इम्यूनिटी और खून बनाने के लिए जरूरी होता है।

लेप्टोमेनिंजियल मेटास्टेसिस का निदान करना बेहद चुनौतीपूर्ण

65 वर्षीय महिला का अचानक शून्य में एकटक देखते रहना और प्रतिक्रिया कम हो जाना शुरुआत में एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल समस्या प्रतीत हो रहा था। लेकिन वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स डॉक्टरों ने उसके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास मौजूद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड में कैंसर की घातक कोशिकाएं पाईं, जिससे पहले सफलतापूर्वक उपचारित कैंसर की एक अत्यंत दुर्लभ पुनरावृत्ति का पता चला। परिजनों ने महिला के व्यवहार में अचानक आए बदलाव को देखा। वह किसी से बातचीत किए बिना लगातार शून्य में एकटक देखती रहती थी। उसे संक्रमण, कमजोरी, दौरे (सीज़र) या स्ट्रोक जैसे कोई स्पष्ट लक्षण नहीं थे। इसलिए शुरुआत में उसकी इस स्थिति के पीछे किसी गंभीर बीमारी की आशंका नहीं थी। वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स, मुंबई सेंट्रल की न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. शीतल गोयल के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने विस्तृत न्यूरोलॉजिकल जांच शुरू की। परिजनों से बातचीत के दौरान पता चला कि 15 वर्ष पहले महिला को स्तन कैंसर (ब्रेस्ट कैंसर) हुआ था। उस समय उनका सफलतापूर्वक इलाज किया गया था और अगले पांच वर्षों तक नियमित फॉलो-अप में भी कैंसर दोबारा होने के कोई संकेत नहीं मिले थे। हालांकि महिला कई वर्षों से कैंसर-मुक्त थी, फिर भी डॉ. गोयल को लगा कि उनके लक्षण किसी सामान्य न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पूरी तरह मेल नहीं खाते। इसलिए उन्होंने आगे की विस्तृत जांच कराने का निर्णय लिया। ‘इस मरीज में शुरुआत में कोई स्पष्ट

लक्षण नहीं थे। वह केवल लगातार एकटक देख रही थीं और उनकी प्रतिक्रिया कम हो गई थी। लेकिन कुछ सूक्ष्म चिकित्सीय संकेतों ने हमें यह महसूस कराया कि मामला सामान्य नहीं है। न्यूरोलॉजी में मामूली दिखने वाले लक्षण भी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं। इसलिए हमने हर छोटी-से-छोटी संभावना की भी गहन जांच की,’ वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स, मुंबई सेंट्रल की न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. शीतल गोयल ने बताया। जांच के तहत डॉक्टरों ने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड की जांच कराई। मात्र दो दिनों में आई पैथोलॉजी रिपोर्ट में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास मौजूद द्रव में कैंसर की घातक कोशिकाएं पाई गईं। इससे लेप्टोमेनिंजियल मेटास्टेसिस नामक दुर्लभ स्थिति का निदान हुआ। इस अवस्था में कैंसर की कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (सेंट्रल नर्वस सिस्टम) को ढकने वाली झिल्लियों तक फैल जाती हैं। इसके बाद किए गए FDG PET-CT स्कैन में मस्तिष्क में सक्रिय कैंसर या पहले हुए स्तन कैंसर की पुनरावृत्ति का कोई प्रमाण नहीं मिला। केवल हड्डियों में कुछ छोटे संदिग्ध परिवर्तन दिखाई दिए, जबकि शरीर के अन्य हिस्सों में कैंसर फैलने के कोई सबूत नहीं मिले। डॉ. गोयल ने आगे कहालेप्टोमेनिंजियल मेटास्टेसिस का निदान करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि मरीजों में शुरुआत में अस्पष्ट न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखाई देते हैं और सामान्य इमेजिंग जांच में भी समस्या स्पष्ट नहीं होती। ऐसे मामलों में डॉक्टरों का चिकित्सीय संदेह, समय पर की गई जांच और सटीक निदान अत्यंत महत्वपूर्ण होते है। समय पर निदान होने से उचित उपचार जल्द शुरू किया जा सकता है।

आज का राशिफल

मेष राशि - आज का दिन आपके लिए मौज-मस्ती से भरा रहने वाला है। आप अपने शौक और विलासिता की चीजों पर अच्छा-खासा धन खर्च कर सकते हैं, इसलिए बजट का विशेष ध्यान रखें। नौकरी में कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, जो भविष्य में काम आएगी। किसी से भी कोई गोपनीय या जरूरी जानकारी शेयर करने से बचें।

वृषभ राशि - वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार और बढ़िया रहने वाला है। आपको अपने पुराने अनुभवों का पूरा फायदा कार्यक्षेत्र में मिलेगा।
प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो कल उसके पूरा होने की प्रबल संभावना है।

मिथुन राशि - आज आपको अपने कामों को थोड़ा संभलकर करने की आवश्यकता है। मेहनत से बिल्कुल जी न चुराएं और अपने भीतर के आलस्य को पूरी तरह दूर भगाएं। कल आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि, बातचीत के दौरान सावधानी रखें, आपकी किसी बात का कोई बुरा मान सकता है।

कर्क राशि - आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाले है। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर सगे-संबंधियों के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने से मन खुश रहेगा। लेन-देन से संबंधित मामलों को लेकर कल किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं। जीवनसाथी की ओर से उपहार मिल सकता है।

सिंह राशि - सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी खर्चों से भरा रहने वाला है। बढ़ते खर्चों के कारण मन में थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन बेवजह तनाव लेने से बचें। कार्यक्षेत्र में तरक्की की राह में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन किसी सहयोगी से कोई भी बात बहुत सोच-समझकर बोलें। काम को योजना बनाकर पूरा करें।

कन्या राशि - आज का दिन आपके लिए परोपकार और धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आप अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपने सभी कामों को समय पर पूरा करेंगे। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद या नई जिम्मेदारी की प्राप्ति हो सकती है। संतान के करियर से जुड़ी जो समस्याएं चल रही थीं, वे कल दूर होंगी।

तुला राशि-तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े काम करने वाले जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कल कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। धन से जुड़े मामलों में सावधान रहें; जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर बाद में पछतावा हो सकता है।

वृश्चिक राशि – आज का दिन आपके प्रभाव और प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए सम्मान और नई पहचान मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी जरूरी काम के सिलसिले में अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। बॉस से कहासुनी होने की आशंका है, इसलिए कल दफ्तर में चुप रहना ही बेहतर होगा।

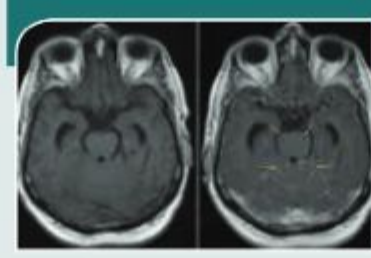

धनु राशि- धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा टेंशन और मानसिक चिंताओं से भरा रह सकता है। विरोधी आपको परेशान करने या आपके काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, सतर्क रहें। आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन काम से जी न चुराएं और संयम बनाए रखें।

मकर राशि - आज का दिन आपके लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है। आपके भौतिक सुख-साधनों में वृद्धि होगी और जीवन में सकारात्मकता आएगी। वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपने काम को लेकर सहयोगियों से खुलकर बातचीत कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है।

कुंभ राशि- कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य और शांतिपूर्ण रहेगा। दान, पुण्य और धर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा।

मीन राशि- आज का दिन आपके लिए सुखमय और आनंद से भरा रहने वाला है। आप अपने मधुर व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे, जिससे मित्रों की संख्या बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपका बोलबाला रहेगा और आपकी लीडरशिप की सराहना होगी। तरक्की की राह में आ रही सभी बाधाएं कल दूर हो जाएंगी।

श्री जगन्नाथ मंदिर और ध्वज की महिमा

सनातन धर्म में कहा जाता है कि केवल भक्त ही भगवान से मिलने नहीं जाते, भगवान भी भक्तों से मिलने आते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ओडिशा के पुरी में देखने को मिलता है; जहां भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान जगन्नाथ कलयुग में मनुष्य की पीड़ा हरने वाले एक साक्षात देव हैं। ओडिशा के पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रहते हैं। इसीलिए इसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। इस बैकुंठ के बारे में जानना भी बहुत दिलचस्प है। रोचक है और अद्भुत है।

विग्रह के उत्पत्ति की कथा

कहते है सतयुग मे राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन उन्हें स्वप्न आया कि पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी आज की पुरी मे समुद्र के किनारे नील माधव के रूप मे भगवान विराजमान है। राजा ने वहां जाकर देखा तो उन्हें एक नीले रंग की मूर्ति मिली। कुछ समय बाद वह मूर्ति भी गायब हो गई। तब भगवान ने फिर उनसे स्वप्न में कहा – "हे राजा, समुद्र के किनारे तुम्हें एक दारू का लड्ढा मिलेगा। उसी से मेरी मूर्ति बनवाओ।" राजा को सच में समुद्र से एक विशाल लकड़ी का लट्ठा मिला। उन्होंने देश भर के कारीगर बुलवाए पर कोई भी उसे काट नहीं पाया। तब एक बूढ़े बढ़ई के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा आए और उन्होंने शर्त रखी – "मैं 21 दिन में मूर्ति बनाऊंगा, पर इस बीच कोई दरवाजा नहीं खोलेगा।"
15 दिन बाद रानी की जिद पर दरवाजा खोल दिया गया। अंदर विश्वकर्मा जी गायब थे और मूर्तियाँ अधूरी थी – बिना हाथ-पैर की। तब आकाशवाणी हुई कि "यही मेरा रूप है। कलयुग मे मेरी इसी रूप मे पूजा होगी।" उसी दिन से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की बिना हाथ-पैर वाली लकड़ी की मूर्तियाँ पुरी मे विराजमान है। मान्यता है कि श्री कृष्ण का हृदय आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति मे धड़कता है। इसीलिए इन्हें 'दारू ब्रह्म' कहते है।
पुरी का जगन्नाथ मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसका नील चक्र और ध्वज है।
मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगता है वह हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। शाम को पुजारी रोज ध्वज बदलते है। मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज न बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या हवाई जहाज भी नही उड़ता। बचपन से सुनते आये है कि भारत मे चार धाम है – बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथ पुरी। मान्यता है कि भगवान विष्णु बद्रीनाथ मे ध्यान लगाते है, रामेश्वरम मे स्नान करते है, पुरी मे भोजन करते है और द्वारका मे विश्राम करते है।

श्री जगदीश महाप्रभु जी की प्रसिद्ध द्वादश यात्राएं

पुरी मे साल भर भक्तो का तांता लगा रहता है। यहाँ हर महीने कोई न कोई उत्सव होता है। उनमें से 12 विशिष्ट उत्सव रूप में पालन होता है ,जो द्वादश यात्रा के नामो से प्रचलित है इस बारे मे नीलाद्री मे एक श्लोक प्रचलित है –
" मंचेस्नानं रथवर गति शयनं चायनद्वयं पार्श्ववृति शयन निवृति प्राबर :पुष्पपूजा। दोल कैलिर्दमनक महदक्षपूजा तृतीया चैत्रयात्रा विधिनिगदिता द्वादशेयं नरेन्द्र ।।"

श्लोक वर्णित द्वादश यात्रा हैं-

(1) चन्दन यात्रा (2) स्नान यात्रा (3) रथ यात्रा या श्रीगुण्डिचा यात्रा (4) हरिशयन एकादशी यात्रा (5) दक्षिणायन यात्रा (6) पार्श्वपरिवर्तन यात्रा (7) हरिउत्थापन (देवोत्थापन) यात्रा (8) पुष्याभिषेक यात्रा (9) प्रावण षष्ठि (ओढ़ण षष्ठि) यात्रा (10) मकरसंक्रान्ति यात्रा (11) दोल यात्रा (12) दयणाचोरि (दमनक चतुर्दशी) यात्रा ।

इन यात्राओं में से कुछ जगत प्रसिद्ध यात्राओं का वर्णन

1. चंदन यात्रा - यह यात्रा वैशाख शुक्ल तृतीया से 42 दिन तक होती है। नरेंद्र सरोवर में यह यात्रा 21 दिन की होती है। इसे बाहर चंदन यात्रा कहते है। श्री मंदिर के भीतर 21 दिन तक यह यात्रा होती है। इसे भीतर चंदन यात्रा कहते है। इस प्रारंभिक तिथि को अक्षय तृतिया भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन श्री जगन्नाथ जी के प्रतिनिधि रामकृष्ण , मदन मोहन, लक्ष्मी, सरस्वती और पंचपांडव, श्रीलोकनाथ, श्रीयमेश्वर ,श्रीकपालमोचन , श्रीमारकंडेश्वर एवं श्रीनीलकण्ठेश्वर अपनी अपनी पालकी पर बैठकर जलविहार के लिए नरेंद्र तालाब तक ले जाये जाते हैं । इसके बाद इन देवी देवताओं को सुसज्जित चाप (नाव) में बैठाकर सरोवर की एक ओर से दूसरे छोर तक घुमाया जाता है। बाद मे देवी देवताओं को सरोवर के बीच अवस्थित चंदन घर मे लाकर वहां सुव्यवस्थित जल से कुछ समय तक रखा जाता है। इसके बाद रामकृष्ण एवं मदनमोहन सिंहासन को आते है और यहां माण्डुअ(एक प्रकार का पीठा) भोग अर्पण किया जाता है । बाद मे एक बार फिर नाव मे बैठकर घूमने के बाद श्री मंदिर वापस आते हैं ।

2. स्नान यात्रा - हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा (देव स्नान पूर्णिमा) के दिन श्री जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। इसके बाद 15 दिन तक भगवान बीमार होकर "अनासर" मे रहते हैं।

3. रथ यात्रा - श्री जगन्नाथ जी की सारी यात्राओं मे रथ यात्रा या गुण्डिचा यात्रा सर्वश्रेष्ठ है । पुरी की रथ यात्रा भारत तथा विदेश मे भी मशहूर है । यह यात्रा अषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को होती है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, बड़े भाई बलभद्रजी बहन सुभद्रा देवी, सुदर्शन और मदन-मोहन मूर्तियों को पहण्डि बिजे कराके विविध कपड़ों से सुसज्जित तीनों रथों पर बैठाया जाता है । इसके बाद ही पुरी के राजा हाथी घोड़ा पालकी आदि सजावट के साथ वहां आते है और रथों पर सोने की झाडू लगाकर चंदन छिड़कते हैं।
उल्टा रथ / बहुड़ा यात्रा- पूरे 9 दिनों के बाद अषाढ़ शुक्ल दशमी को भगवान वापस मंदिर लौटते हैं।
सुनाबेश – उल्टा रथ के दिन भगवान को सोने के गहने पहनाए जाते हैं।
यात्रा के दिन तीनों भगवानों को नए-नये कपड़े पहनाकर बड़े-बड़े रथों मे बिठाया जाता है। फिर पुरी के राजा खुद आकर सोने की झाडू से रास्ता साफ करते है। इसे छेरा पहरा कहते है। उसके बाद भक्त लोग 'जय जगन्नाथ' के नारे लगाते हुए रथ की रस्सी खींचते हैं। ऐसी लोक मान्यता है कि जो भक्त एक बार रथ यात्रा मे शामिल हो जाए, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है:
"रथस्थो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते"_ (स्कंद पुराण)
अर्थात रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरी मे आना केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है; यह पर्यटन का भी मुख्य केंद्र माना गया है।

– डॉ. संगीता अजय पांडेय

यूनिवर्सिटी में शुरू होगा यूटीडी, सिर्फ कल्याण कॉलेज में बना एंट्रेंस के लिए एग्जाम सेंटर

पांच विषय में एमएससी के तीन शिफ्ट में हुई परीक्षा

भिलाई। छत्तीसगढ़ के एजुकेशन हब यानी दुर्ग-भिलाई से गुड न्यूज है। यहां स्थित शासकीय विश्वविद्यालय में यूटीडी शुरू किया जा रहा है। इसके लिए शुक्रवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इसके लिए एकमात्र सेंटर कल्याण कॉलेज को बनाया गया था।

दुर्ग के शासकीय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय (दुर्ग यूनिवर्सिटी) में यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट (यूटीडी) शुरू किया जा रहा है। इसके लिए शुक्रवार को एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया गया। एंट्रेंस एग्जाम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा एकमात्र सेंटर सेक्टर-7 स्थित कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय को बनाया गया था। यहां तीन शिफ्ट में परीक्षाएं आयोजित हुई।

इन विषयों में होगा एमएससी- यूटीडी में साइंस स्ट्रीम के अलग-अलग विषय में प्रवेश पाने बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम में भाग लिया। इसमें एमएससी मैथ्स, एमएससी बॉटनी, एमएससी फिजिक्स, एमएससी जूलॉजी और केमेस्ट्री में एमएससी करने के लिए ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स शामिल हुए।

1455 अभ्यर्थियों के लिए थी सीटिंग- पांच विषयों में एमएससी करने के लिए एक हजार चार सौ 55 (1,455) अभ्यर्थियों के लिए सीटिंग की व्यवस्था की गई थी। तीन शिफ्ट की परीक्षा में कुल 768 अभ्यर्थी शामिल हुए जबकि 683 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे।

परीक्षा के लिए लगा रहा पूरा अमला- कल्याण कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ.विनय शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय में यूटीडी शुरू होना अंचल के लिए भाग्य और खुशी की बात है। लेकिन पहली बार आरंभ हो रहे यूटीडी में एंट्रेंस एग्जाम के लिए कल्याण कॉलेज को सेंटर बनाया जाना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। एंट्रेंस के लिए कॉलेज का संपूर्ण अमला सुबह से देर शाम तक मुस्तैदी से तैनात रहा। कॉलेज के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ.लखन चौधरी, डॉ.सलीम अक़ील, डॉ.सुधीर शर्मा, डॉ.ईश्वर सिंह बरगाह, डॉ.रवीश कुमार सोनी और डॉ.गुणवंत चंद्रौल के निर्देशन में तमाम वीक्षक, कार्यालयीन स्टाफ, सहायक कर्मचारियों से लेकर सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

विधायक रिकेश ने उठाया राशन वितरण में गड़बड़ी का मुद्दा, खाद्य मंत्री बोले- नगद भुगतान नहीं, सिर्फ 4 शिकायतें मिलीं

भिलाई नगर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कथित अनियमितताओं का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने खाद्य मंत्री से पूछा कि क्या वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों में हितग्राहियों को राशन कार्ड पर मिलने वाले चावल की जगह नगद राशि दी जा रही है और गरीबों के हिस्से का चावल अवैध रूप से बाजार में बेचा जा रहा है।

विधायक ने यह भी जानना चाहा कि इस प्रकार की कुल कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुईं, उन पर क्या जांच और कार्रवाई की गई, दोषी राशन दुकानदारों एवं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कानूनी कदम उठाए गए तथा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है।

खाद्य मंत्री का जवाब- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने सदन में स्पष्ट किया कि वैशाली नगर क्षेत्र में चावल के स्थान पर हितग्राहियों को नगद भुगतान किए जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल के अवैध परिवहन से संबंधित कुल 4 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है। कार्रवाई का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट में उपलब्ध कराया गया है।

मंत्री ने यह भी कहा कि पात्र हितग्राहियों को पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी सत्यापन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू है। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है और अनियमितताओं पर नियंत्रण रखा जा रहा है।

विधानसभा में उठा पारदर्शिता का सवाल- विधायक रिकेश सेन ने सरकार से यह भी पूछा कि गरीबों के हक के राशन की कालाबाजारी रोकने और भविष्य में पात्र हितग्राहियों को पूरा राशन सुनिश्चित करने के लिए विभाग कौन से ठोस एवं सुधारात्मक कदम उठा रहा है।

आपको बता दें कि यह मामला विधानसभा में उठने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है।

विधानसभा के शून्यकाल में गूंजा बीएसपी लोहा चोरी का मामला

वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने केंद्रीय एजेंसियों से जांच की उठाई मांग, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा का मुद्दा सदन में प्रमुखता से रखा

भिलाई नगर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पंचम एवं अंतिम दिवस शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भिलाई स्टील प्लांट में पिछले चार दशकों से कथित रूप से जारी लोहा एवं स्क्रैप चोरी के मामले को प्रमुखता से उठाते हुए इसे राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताया। उन्होंने सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए कहा कि यह केवल चोरी का मामला नहीं, बल्कि देश की सार्वजनिक संपत्ति को निरंतर क्षति पहुंचाने वाला संगठित अपराध है, जिसकी निष्पक्ष एवं व्यापक जांच आवश्यक है।

संगठित गिरोह की भूमिका की हो निष्पक्ष जांच- शून्यकाल में अपनी बात रखते हुए विधायक रिकेश सेन ने कहा कि वर्षों से एक संगठित गिरोह, प्लांट के कुछ अधिकारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों की कथित मिलीभगत से करोड़ों रुपये मूल्य का लोहा और स्क्रैप सुनियोजित तरीके से बाहर निकालता रहा है।

उन्होंने कहा कि अब तक सामने आए मामलों में अधिकांशतः क्रेन ऑपरेटर, ट्रक-ट्रेलर चालक अथवा निचले स्तर के कर्मचारियों तक ही कार्रवाई सीमित रही, जबकि पूरे नेटवर्क का संचालन करने वाले कथित सरगनाओं तक जांच और कानूनी कार्रवाई नहीं पहुंच सकी। इसी कारण ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पाया।

राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा का प्रश्न- विधायक सेन ने सदन में कहा कि भिलाई स्टील प्लांट देश की महत्वपूर्ण औद्योगिक धरोहर है और वहां से होने वाली कथित चोरी राष्ट्रीय संपत्ति को प्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर उन सभी लोगों की जवाबदेही तय की जाए जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इसमें संलिप्त रहे हों, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सके।

केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग- रिकेश सेन ने सदन में यह भी कहा कि मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जानी चाहिए, जिससे पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके और वास्तविक जिम्मेदार व्यक्तियों तक कानूनी कार्रवाई पहुंच सके। ऐसे मामलों में केवल निचले स्तर पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे तंत्र की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

विधानसभा की कार्यवाही में दर्ज हुआ मुद्दा- शून्यकाल के दौरान उठाए गए इस विषय को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित सदन ने गंभीरता से सुना। भिलाई स्टील प्लांट में कथित करोड़ों रुपये के लोहा चोरी का यह मामला विधानसभा की कार्यवाही में दर्ज हुआ, जिससे इस विषय को राज्य की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था में औपचारिक रूप से स्थान मिला।

पूर्व में भी विभिन्न संवैधानिक एवं जांच एजेंसियों को सौंप चुके हैं शिकायत- विधायक रिकेश सेन इस विषय को पहले भी विभिन्न स्तरों पर उठाते रहे हैं। उन्होंने प्रकरण से संबंधित शिकायतें सीबीआई, ईओडब्ल्यू, ईडी, एसीबी, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भेजकर विस्तृत जांच की मांग की है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

विधानसभा से लोकसभा तक पहुंचा मुद्दा- राज्य स्तर पर मामला उठने के बाद अब यह विषय राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आने लगा है। भारत सरकार के स्टील मंत्रालय से संबंधित समिति में महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी ने भी भिलाई स्टील प्लांट में कथित लोहा चोरी का मुद्दा उठाया है। विधायक रिकेश सेन की पहल के बाद यह विषय अब सांसद के माध्यम से लोकसभा तक भी पहुंच रहा है, जिससे मामले की व्यापक जांच और राष्ट्रीय स्तर पर विचार की संभावना और मजबूत हुई है।

भगवान जगन्नाथ ने जन कल्याणार्थ निकले भ्रमण पर

गाजीपुर। आषाढ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितिया तिथि गुरूवार को देर रात्रि भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा का आयोजन विभिन्न स्थानो से किया गया। भगवान जगन्नाथ 15 दिन बीमारी के उठकर स्वस्थ्य होकर जनता जनार्दन के दर्शन देने एव जन कल्याण के लिए भ्रमण पर निकलते हैं तो लोग भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, बहन सुभद्रा के दर्शन कर सभी श्रद्धालुगण के कुशलक्षेम की कामना लेकर लोग पूजा अर्चन किये। श्रद्धालु अपने अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं और वर्ष में एक बार निकलने वाले रथयात्रा का पूरे मनोयोग से उनका इंतजार करते हैं और भगवान के रथ आने पर उनका भव्य रूप से घड़ीघंटा, शंखनाद के साथ पूजा अर्चना आरती करते हैं और जामुन आम चना बतासे गुलगुले का भोग लगाकर प्रसाद वितरण कर अपने भाव प्रकट करते हुए जनकल्याण का संदेश देते है। इसी क्रम में स्टीमरघाट स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाले रथ का आरती पूजन पंडित राजेश पाण्डेय ने किया और रथयात्रा स्टीमर घाट से निकलकर टेढ़ी बाजार, गायत्री नगर, झंडातर, मारकीनगज होते हुए चीतनाथघाट, टाउनहॉल, बैजनाथ चौक, लाल दरवाजा, मिश्रबाजार शिवमंदिर पर पहुचा। वही दूसरी रथयात्रा का पूजन गोपाल पाण्डेय ने किया जो रथयात्रा हरिशंकरी से निकलकर लालदरवाजा होते हुए मिश्रबाजार में शिव मंदिर पर मिलते हैं और भजन कीर्तन हुआ। दोनों अपने अपने मंदिर मे वापस वीराजमान हो जाते हैं। वही विखयात पवहारी बाबा आश्रम कुर्था से भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा की झांकी निकाली गयी जो प्राइमरी स्कूल कुर्था खेल के मैदान मे पहुचा और मेला का आयोजन हुआ। जिसमें हजारो भक्तो ने दरशन पूजन किया और रात्रि पहर पंडित अमरनाथ तिवारी ने आरती पूजन कर मेला का समापन किया। इस अवसर पर प्रेम प्रकाश, प्रभात, हृदय प्रकाश, नितिन अग्रहरि, कृपा शंकर राय, अजय कुमार तिवारी, गोपाल चौधरी किशन चौधरी रामा चौधरी अभिषेक, लवकुश बड़े महाराज, बच्चा तिवारी, संजय केसरी, आदित्य प्रकाश आर्य, अशोक अग्र हारी, संजय यादव, श्रीप्रकाश केशरी, श्रीराम यादव, श्रीराम बरनवाल अशोक जायसवाल, संजय जायसवाल आदि सैकडो भक्त उपस्थित रहे।

सीएम हेल्पलाइन की मदद से दूर हुआ अंधेरा, जिले के संतोषी नगर वार्ड में त्वरित कार्रवाई से फिर जगमगाई स्ट्रीट लाइटें

दुर्ग। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित 'सीएम हेल्पलाइन 1076' आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के माध्यम से सुशासन को धरातल पर मजबूत कर रही है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 33, संतोषी नगर से सामने आया है। यहाँ कई दिनों से स्ट्रीट लाइटें बंद होने के कारण शाम ढलते ही पूरे क्षेत्र में अंधेरा पसर जाता था, जिससे न केवल राहगीरों, महिलाओं व बच्चों को आवागमन में भारी असुविधा होती थी, बल्कि अंधेरे की आड़ में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ने से क्षेत्रवासियों में असुरक्षा की भावना भी पनप रही थी। इस सार्वजनिक समस्या के समाधान के लिए स्थानीय जागरूक नागरिक बोल बम गुप्ता ने 'सीएम हेल्पलाइन 1076' पर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर संबंधित विभाग ने त्वरित संज्ञान लेते हुए कुछ ही दिनों के भीतर बंद पड़ी सभी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कर उन्हें पुनः चालू कर दिया। जिला प्रशासन की इस त्वरित कार्यप्रणाली ने साबित कर दिया है कि अब आम जनता की समस्याओं को फाइलों में दबाया नहीं जाता, बल्कि उन पर तत्काल एक्शन लिया जाता है। डिजिटल माध्यम से मिली इस राहत ने आम नागरिकों और शासन के बीच के फासले को पूरी तरह से मिटा दिया है। वार्ड में रोशनी लौट आने से जहाँ स्थानीय निवासियों को अब रात के समय सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल रही है और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को बोल बम समिति के संयोजक जितेन्द्र वर्मा ने 17 अगस्त को आयोजित विशाल बोल बम कांवर यात्रा में किया आमंत्रित

पाटन। बोल बम कांवर यात्रा समिति, पाटन के संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य भेंट कर 17 अगस्त को आयोजित होने वाली विशाल बोल बम कांवर यात्रा महोत्सव में आमंत्रण किया। इस अवसर पर वर्मा ने मुख्यमंत्री जी को यात्रा की रूपरेखा, तैयारियों एवं आयोजन के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन के तीसरे सोमवार को पाटन से टोलाघाट तक हजारों शिवभक्तों की सहभागिता से भव्य कांवर यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन गजेंद्र यादव प्रमुख रुप से उपस्थित थे। समिति के संयोजक जितेन्द्र वर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया कि बोल बम कांवर यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता, सेवा, अनुशासन एवं जनआस्था का विराट उत्सव है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए बोल बम के जयघोष के साथ पाटन से टोलाघाट तक पैदल यात्रा करेंगे। आयोजन को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने के लिए चिकित्सा सहायता, पेयजल, भोजन, विश्राम, सुरक्षा, यातायात एवं स्वच्छता सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए जितेन्द्र वर्मा एवं बोल बम कांवर यात्रा समिति के सदस्यों को आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समिति की ओर से अधिक से अधिक श्रद्धालुओं, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, युवा मंडलों, महिला समूहों, जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्रवासियों से 17 अगस्त को पाटन से टोलाघाट तक निकलने वाली इस भव्य कांवर यात्रा में सहभागिता कर आयोजन को ऐतिहासिक एवं सफल बनाने की अपील की गई।

फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026

दुर्ग। खरीफ मौसम के दौरान किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की अनिश्चितता से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन की प्रक्रिया 12 जुलाई से शुरू हो चुकी है। सभी किसान अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 का इंतजार किए बिना समय पर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस साल अलनीनो के प्रभाव के कारण अनियमित या कम बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसी स्थिति में संभावित नुकसान से बचने के लिए फसल बीमा किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा।

कृषि विभाग द्वारा बताया गया है कि योजना के तहत जिले में किसान भाई अधिसूचित फसलों धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन, तुअर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, कोदो, कुटकी तथा रागी का बीमा करा सकते हैं। कृषक बैंक, वित्तीय संस्थान, लोक सेवा केंद्र, या स्वयं सीधे भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर अपना पंजीयन करा सकते हैं। जिस हेतु आवश्यक दस्तावेज नवीनतम आधार कार्ड, नवीनतम बी-1 और पी-2 की कॉपी, बैंक पासबुक के मुख्य पृष्ठ की फोटोकॉपी, फसल बुवाई का प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा पत्र, बटाईदार/कास्तकार/साझेदार किसानों के लिये फसल साझा/ कास्तकार का घोषणा पत्र तथा चालू मोबाइल नंबर है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में चार प्रमुख जोखिम फसल की बुवाई/रोपाई (प्रतिकूल मौसम अवस्थाओं के कारण) नहीं होने, स्थानीयकृत आपदाएं (ओलावृष्टि, जलभराव आदि) व फसल कटाई के उपरांत खेत में काटकर व फैलाकर गठरों में बांधकर सुखाने के लिये रखी गई फसल में होने वाली क्षति एवं फसल कटाई के बाद उपज के आंकड़ो के आधार पर क्षति को शामिल किया गया है। यदि किसी भी आपदा के कारण फसल को नुकसान पहुंचता है, तो किसानों को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके लिए कृषक केंद्र सरकार के टोल-फ्री नंबर 14447 (कृषि रथक पोर्टल व हेल्पलाइन) पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा पीएमएफबीवाई के अधिकृत व्हाट्सएप नंबर 7065514447 पर भी विवरण भेजा जा सकता है। किसान सीधे ही पर जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। एवं गूगल प्ले स्टोर से क्रॉप इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड करके किसान स्वयं अपनी फसल हानि का पूरा विवरण दर्ज कर सकते हैं।

विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस प्रकरणों का होगा आपसी समझौते से निराकरण

दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के0 विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में आज दिनांक 18 जुलाई 2026 (शनिवार) को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (चेक बाउंस प्रकरण) से संबंधित मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस प्रकरणों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर शीघ्र, सरल एवं प्रभावी निराकरण कर पक्षकारों को दीर्घकालीन न्यायिक प्रक्रिया से राहत प्रदान करना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने ऐसे सभी चेक धारकों, चेक जारीकर्ताओं, पक्षकारों तथा संबंधित अधिवक्ताओं से अपील की है कि जिनके धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं, वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से अथवा संबंधित न्यायालय से संपर्क कर विशेष लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं तथा आपसी समझौते के माध्यम से अपने विवाद का स्थायी एवं सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करें। उक्त संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा सम्पूर्ण दुर्ग जिले में विभिन्न माध्यमों से व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार भी किया गया है।

विशेष लोक अदालत को सफल बनाने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत तथा आकांक्षा राठौर एवं अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की विशेष टीम गठित की गई थी। टीम द्वारा संबंधित अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों से निरंतर संपर्क स्थापित कर, आपसी संवाद एवं समझौते के लिए प्रेरित करते हुए अधिकाधिक प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण निराकरण के उद्देश्य से अथक एवं सराहनीय प्रयास किए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विश्वास व्यक्त किया है कि इन प्रयासों से विशेष लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण संभव होगा।

विशेष लोक अदालत में समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण होने से पक्षकारों के समय, धन एवं श्रम की बचत होती है, आपसी संबंधों में सुधार होता है तथा विवाद का शीघ्र एवं संतोषजनक समाधान संभव हो पाता है। लोक अदालत में पारित निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा उसका विधिक महत्व न्यायालय के निर्णय के समान होता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित चेक बाउंस प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें तथा न्याय सुलभ, त्वरित एवं सरल बनाने की इस पहल में सहभागी बनें।

जिले में वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायालय की होगी स्थापना

दुर्ग। जिले के उद्यमियों, व्यापारियों एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए राहत भरी खबर है। जिले से संबंधित वाणिज्यिक विवादों की त्वरित सुनवाई एवं शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। केबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव की पहल से दुर्ग में वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना होगी।। इसके तहत दुर्ग जिले से उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय नामित करने की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वर्तमान में द्वितीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), दुर्ग के न्यायालय में होने वाली वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई अब चतुर्थ सिविल जज (सीनियर डिवीजन), दुर्ग के न्यायालय में की जाएगी। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 3 की उपधारा (1), (1-ए), (2) एवं (3) के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त न्यायालय को सिविल जज स्तर के विशेष वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में नामित करते हुए अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। इस निर्णय से दुर्ग जिले के उद्यमियों, व्यापारियों एवं उद्योगों से जुड़े वाणिज्यिक विवादों का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित होगा।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। डाक पंजीयन क्रमांक- सीजी/दुर्ग/लोकतंत्र प्रहरी/2026-28, Email : loktantraprahrinews@gmail.com